RNI No. : TNHIN/2013/52520 | वर्ष - 14 | अंक - 7 | पृष्ठ - 8 | रु. 5/- | चेन्नई » बुधवार » 29-07-2026 | www.dakshinbharat.com | Email : chennai@dakshinbharat.com

# दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 युवाओं के हर सपने को पूरा कर रही डबल इंजन सरकार : शर्मा

6 उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरणों की आहट और कांग्रेस!

7 रेखा को मिलेगा आईएफएफएम में खास सम्मान

## फर्स्ट टेक

### फ्रांस में जंगल में आग : 4000 लोगों को पर्यटन स्थल से निकालने का आदेश

लेज-कैप-फेरेट (फ्रांस)/एपी। फ्रांस के अधिकारियों ने मंगलवार को खराब होते मौसम के कारण जंगल की आग और भड़कने का खतरा बढ़ने के बीच, देश के अटलांटिक तट पर स्थित लकानाउ क्षेत्र के आसपास के कैंप स्थलों, पर्यटकों के ठहरने की जगहों, 'हॉलिडे विलेज और मनोरंजन पार्कों' से लगभग 4,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दिया। गिरोंद क्षेत्रीय प्रशासन ने बताया कि निकासी अभियान लाकानो ओसियन और लाकानो झील के दोनों किनारों पर लागू किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपने आवश्यक सामान साथ ले जाने, आपातकालीन निर्देशों का पालन करने तथा प्रशासन की अनुमति मिलने तक संबंधित क्षेत्रों में वापस नहीं लौटने की अपील की।

### रिजर्व बैंक के पास 880 मीट्रिक टन सोना, धार्मिक स्थानों को लेकर कोई जानकारी नहीं : सरकार

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास 880.52 मीट्रिक टन स्वर्ण भंडार है लेकिन उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि देश के 'धार्मिक स्थानों' या परिवारों के पास कितना सोना है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 26 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास 880.52 मीट्रिक टन स्वर्ण भंडार था। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 को 879.58 मीट्रिक टन, 31 मार्च 2024 को 822.10 मीट्रिक टन स्वर्ण भंडार था। उनसे सवाल किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास वर्तमान में कितना स्वर्ण भण्डार है? इसके साथ ही यह सवाल भी किया गया था कि क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है कि देश में ''धार्मिक स्थानों'' और भारतीय परिवारों में कितना सोना जमा है?

### देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का दिल का दौरा पड़ने से निधन

मुंबई/भाषा। दिग्गज अभिनेता देव आनंद और अभिनेत्री कल्पना कार्तिक के बेटे सुनील आनंद का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वह 70 वर्ष के थे। अभिनेता एवं निर्देशक सुनील आनंद ने वर्ष 1984 में अपने पिता द्वारा निर्देशित फिल्म 'आनंद और आनंद' से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'कार थीफ', 'मैं तेरे लिए' और 'मास्टर' जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें अपने पिता जैसी सफलता नहीं मिल सकी।

| | |
|---|---|
| 29-07-2026 सूर्यास्त 6:37 बजे | 30-07-2026 सूर्योदय 5:55 बजे |
| BSE 76,765.92 ( -69.86 ) | NSE 23,985.35 (-10.61) |
| सोना 14,848 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम | चांदी 235,000 रु. प्रति किलो |

### मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक

epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

**समानता सूत्र**

हम जाति पूछना बंद करें,
ना पूछे धर्म वर्ग आधार।
मिट जाएगा भेद स्वत: ही,
होंगे सम सबके व्यवहार।
आरक्षण उनको देवें,
जो हैं लाचार दीन बीमार।
जिनको इसका लाभ मिल गया,
छोड़ें परहित में अधिकार।।

### जल भराव

गुरुग्राम में मानसूनी बारिश के बाद बजघेड़ा अंडरपास के पास जलभराव वाली सड़क से गुजरते वाहन।

## 'अधिक बल प्रयोग' की वजह से पुलिस की छवि खराब नहीं की जा सकती : न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टिप्पणी की कि विरोध के अधिकार का अभिप्राय 'संप्रभुता' को नुकसान पहुंचाना नहीं है और नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ 20 जुलाई को आयोजित 'चलो संसद' मार्च के दौरान कथित तौर पर ''अत्याधिक बल प्रयोग'' के अधार पर किसी पुलिस अधिकारी की छवि को 'खराब' नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने यह टिप्पणी दिल्ली पुलिस के अपर पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा से एक मामले की जांच वापस लेने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए की। लांबा को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के 'चलो संसद' मार्च के दौरान एक महिला को थप्पड़ मारते हुए देखा गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी।

अधिवक्ता एम. सुफियान सिद्दीकी ने दलील दी कि लांबा के व्यवहार (जैसा कि वीडियो क्लिप में देखा गया है) के कारण, 2025 में कथित तौर पर गैर-कानूनी रूप से हिरासत में लिए जाने की जांच की निष्पक्षता पर से याचिकाकर्ता का भरोसा पूरी तरह से डगमगा गया है। इसलिए, उक्त मामले की जांच किसी स्वतंत्र अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए।

## राष्ट्रपति को मिले 300 उपहारों की नीलामी पांच अगस्त से होगी शुरू

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में दिए गए स्मृति चिन्ह समेत 300 उपहारों की ई-नीलामी पांच अगस्त को शुरू होगी। राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू का चार साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मंगलवार को शुरू की गई यह पहल सार्वजनिक सेवा, समावेशिता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की साझा भावना को दर्शाती है। मुर्मू (68) ने 25 जुलाई 2022 को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति पद पर चार साल पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ई-उपहार के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। इसमें सार्वजनिक नीलामी के लिए राष्ट्रपति को मिले 300 चुने हुए उपहार शामिल हैं। यह नीलामी पांच अगस्त से पांच सितंबर 2026 तक चलेगी। नीलामी से मिलने वाली पूरी राशि सामाजिक कार्यों में सहायता के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नीलामी में शामिल वस्तुओं में से एक ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में दिया गया स्मृति चिन्ह भी है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पेंटिंग, त्रिपुरा स्थित श्री त्रिपुरेश्वरी देवी मंदिर की प्रतिकृति, राजस्थानी लघु चित्रकला और गौतम बुद्ध की फ्रेम वाली पेंटिंग भी नीलामी के लिए उपलब्ध होगी।

## राजग संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए एनसीपीआई सांसद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हुए सांसदों के एक समूह ने पहली बार, मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। 'मंगल मिलन' में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शीर्ष केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सदस्य हाल में अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करने के बाद एनसीपीआई में शामिल हुए थे। हालांकि, वे लोकसभा में तृणमूल सांसदों से अलग बैठ रहे हैं, लेकिन सदन के अध्यक्ष ओम बिरला ने एनसीपीआई को मान्यता देने पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

एनसीपीआई में शामिल होने के बाद, सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राजग के प्रति अपनी निष्ठा जताई। इस समूह के एक प्रमुख नेता, सुदीप बंद्योपाध्याय ने हाल में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। राजग संसदीय दल की बैठक संसद भवन परिसर में हुई। एनसीपीआई की सांसद सायोनी घोष ने कहा, ''मैंने राजग की बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में यह एक अत्यंत ज्ञानवर्धक बैठक थी। आज हमने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर चर्चा की। यह काफी सकारात्मक चर्चा रही।'' उन्होंने लोकसभा में आज चर्चा के लिए पेश किये जाने वाले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक 2026' का संदर्भ देते हुए कहा कि प्रश्नपत्र लीक रोधी इस विधेयक का सभी को समर्थन करना चाहिए।

एक अन्य सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बताया कि यह पहला मौका था जब एनसीपीआई के 20 सांसदों को राजग की 'मंगल मिलन' बैठक में आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा, ''हमें देश की प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों और किसानों के बारे में जानकारी दी गई... जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे हम जनता को भी इन विषयों के बारे में बेहतर तरीके से समझा सकेंगे।''

बैठक में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जे.पी. नड्डा, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, किरेन रीजीजू और राजग के सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि बैठक दो विषयों पर केंद्रित थी, व्यापार और मत्स्य पालन।

# प्रधानमंत्री की पोस्ट हटाने के बाद मेटा के अधिकारी तलब

## सरकार ने कंपनी का स्पष्टीकरण 'खारिज' किया

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनी मेटा के सोशल मीडिया मंच 'फेसबुक' से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'पोस्ट' हटाने के बाद उसके लोक नीति प्रमुख (वैश्विक) को तलब किया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि मेटा ने सरकार से कहा कि उसके स्वचालित 'कंटेंट फिल्टर' में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रधानमंत्री मोदी की 'फेसबुक पोस्ट' हट गई थी। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने पाया कि मेटा का यह स्पष्टीकरण उचित नहीं है तथा इस मामले में और गहन चर्चा की जरूरत है। मामले का अभी निपटारा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि स्वचालित प्रणाली में आई गड़बड़ी के कारण यह त्रुटि हुई है तो मेटा को अपने उपकरणों में सुधार करना चाहिए।

सूत्रों ने बताया कि इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम की संचालक कंपनी) के लोक नीति प्रमुख (वैश्विक) को तलब किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जुलाई को इंस्टाग्राम पर अपनी पहली (सेल्फी) वीडियो साझा की थी। उसे फेसबुक पर भी साझा किया गया था। इस वीडियो में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। हालांकि, बाद में फेसबुक पर इस 'पोस्ट' को हटा दिया गया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने मंच की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।

प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो पर कथित रोक को लेकर मेटा की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर उन्होंने लिखा था कि इससे कंपनी की राजनीतिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। प्रीति गांधी ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री भारत के युवाओं से जुड़ने के लिए अपनी वीडियो जारी करते हैं... और फेसबुक उस पर रोक लगा देता है??? मेटा को यह अधिकार किसने दिया कि वह तय करे कि करोड़ों भारतीय क्या देखें और क्या नहीं देखें?' उन्होंने कहा, ''यह केवल सामग्री पर 'नियंत्रण' नहीं है।

## एआई निर्मित पोस्ट के खिलाफ गडकरी की याचिका पर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह एथनॉल नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ अपलोड किए गए ''अपमानजनक'' 'डीपफेक वीडियो' और कृत्रिम मेधा निर्मित पोस्ट के मामले में

'मेटा', 'एक्स कॉर्प', 'गूगल एलएलसी' और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने केंद्रीय मंत्री के अधिवक्ता संदीप लड्डा को इस दीवानी याचिका की प्रतियां प्रतिवादियों को सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में गडकरी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के प्रसार पर स्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। 'डीपफेक' वीडियो कृत्रिम मेधा (एआई) की मदद से इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उसमें कोई व्यक्ति ऐसी बातें कहता या करता दिखाई देता है, जो उसने वास्तव में कभी नहीं कही। गडकरी ने अपनी याचिका में फर्जी और मनगढ़ंत सामग्री को तुरंत हटाने तथा ऐसी सामग्रियों के प्रसार पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

# आरएएफ ने 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से आठ गोलियां चलाई थीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

> दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं। सीआरपीएफ और आरएएफ ने अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर 20 जुलाई के चलो संसद' मार्च के दौरान जंतर-मंतर के पास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की अनुमति के तहत प्लास्टिक पैलेट गन समेत कई कम घातक हथियारों का इस्तेमाल किया था। अधिकारियों ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि इस घटना की जानकारी संसद मार्ग थाने की सामान्य डायरी (जीडी) में 22 जुलाई को अपराह्न 1 बजकर 24 मिनट पर दर्ज की गई है। यह प्रविष्टि आरएएफ के एक उप कमांडेंट की सूचना पर की गई थी जिसमें कहा गया कि नीली वर्दी वाला यह बल दिल्ली पुलिस के एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) स्तर के अधिकारी के साथ जंतर-मंतर क्षेत्र के जोन-1 में तैनात था।

थाने के अभिलेखों के हवाले से अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई को डीसीपी के निर्देश पर आरएएफ ने 55 नॉन-इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिकल शेल, पांच आंसू गैस के गोले दागे थे। इसके अलावा कम घातक दंगा-रोधी बंदूक से दो और पैलेट गन से भी दो राउंड गोलियां चलाई गईं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आरएएफ की अन्य टुकड़ियों ने अन्य विरोध स्थलों पर भी पैलेट गन का इस्तेमाल किया था या नहीं। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं। सीआरपीएफ और आरएएफ ने अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पैलेट गन के एक राउंड में प्लास्टिक के चार छर्रे होते हैं। ये धातु के उन छर्रों से अलग होते हैं, जो शरीर को भेद सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्लास्टिक के इन छर्रों से अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है।

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग, विशेषकर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और संसद में गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग कर रहा है। नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आहूत इस विरोध मार्च के दौरान दो-तीन प्रदर्शनकारियों के पैलेट लगने से गंभीर रूप से घायल होने की खबरें सामने आई थीं। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सीजेपी ने अपना लगभग एक महीने से जारी आंदोलन वापस ले लिया। इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कई जवान भी घायल हुए थे। सीआरपीएफ के महानिदेशक जी. पी. सिंह ने कहा है कि इन प्रदर्शनों के दौरान हुई कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है।

**जश्न**

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की शर्मिला ढाका और कांस्य पदक जीतने वाली शिल्पा के. शायला अपनी जीत का जश्न मनाती हुईं।

## दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

तोक्यो/एपी। जापान के दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू के कुमामोतो क्षेत्र में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने यह जानकारी दी। एजेंसी ने बताया कि सुनामी की चेतावनी कुमामोतो के पश्चिमी तट पर स्थित निकटवर्ती अरियाके खाड़ी के लिए जारी की गई है। यह क्षेत्र टोक्यो से लगभग 900 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने एक संदेश में उन क्षेत्रों के लोगों से समुद्र तटों से दूर रहने की अपील की, जहां एक मीटर तक ऊंची सुनामी आने का अनुमान है। उनकी सरकार ने स्थिति की जानकारी जुटाने, संभावित नुकसान का आकलन करने और आवश्यकता पड़ने पर बचाव अभियान की तैयारी के लिए एक कार्यबल का गठन किया है।

# दिल्ली में भारी बारिश से जलभराव और यातायात जाम

## मौसम विभाग ने 'रेड अलर्ट' जारी किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** दिल्ली में मंगलवार सुबह भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, व्यस्त बाजारों में घुटनों तक पानी भर गया और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। शहर में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिनभर बादल छाए रहने और भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले कुछ घंटों के लिए बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ तेज बारिश होने को लेकर 'रेड अलर्ट' जारी किया है।

सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। कनॉट प्लेस, जनपथ, लुटियंस दिल्ली की कई सड़कों, भारत मंडपम रोड, बाराखंभा रोड, आईटीओ के पास मथुरा रोड, कालिंदी कुंज और अन्य निचले इलाकों में जलभराव होने की सूचना मिली। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की खबरों के बीच लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें मिंटो ब्रिज पर यातायात सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन मिंटो ब्रिज पर जनजीवन उसी गति से चल रहा है। हमारा प्रयास यही है कि मानसून केवल एक मौसम बनकर रहे, लोगों के लिए परेशानी का कारण न बने। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच एक्स' पर दिल्ली के सबसे व्यस्त थोक बाजारों में से एक सदर बाजार का एक वीडियो साझा किया।

वीडियो में दिख रहा है कि वहां बारिश का पानी कमर तक भर गया है, तथा स्कूली बच्चों, कार्यालय जाने वालों और खरीदारों को जलमग्न सड़कों से होकर गुजरना पड़ रहा है। विपक्षी नेता ने सोशल मीडिया मंच पर कहा, दिल्ली के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक सदर बाजार में स्कूली बच्चे कमर तक भरे बारिश के पानी से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की ओर से साझा किए गए कुछ पोस्ट के अनुसार, ग्रेटर कैलाश-2 से सावित्री सिनेमा, चिराग दिल्ली, हौज खास और आरके पुरम तक भारी यातायात जाम की सूचना मिली। वहीं, एमबी रोड के दोनों कैरिजवे पर संगम विहार से खानपुर तक भी वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। जलभराव के कारण कई प्रमुख सड़कों पर यातायात जाम की स्थिति देखने को मिली। इनमें शंकर विहार के पास एनएच-8, जाकिर हुसैन रोड, दिल्ली कैंट-नरैना फ्लाईओवर-मायापुरी मार्ग, आईटीओ, पुरानी रोहतक रोड, मधुबन चौक-नेताजी सुभाष प्लेस मार्ग, पीरागढ़ी, एम्स के पास एनएच-48, दिल्ली-नोएडा रोड, कालिंदी कुंज और विकास मार्ग समेत अन्य प्रमुख सड़कें शामिल हैं।

### शिवसागर के लोगों ने बयां की भयावह कहानी

# 12 घंटे दीवान पर बैठकर बुजुर्गों की बची जान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**शिवसागर/भाषा।** असम के शिवसागर जिले में बाढ़ के दौरान 70 वर्ष से अधिक उम्र के दंपति मुकुल और बोंटी बेजबरुआ को अपने घर में घुसे बाढ़ के पानी के बीच करीब 12 घंटे तक एक लकड़ी के दीवान पर बैठकर जान बचानी पड़ी। वे बाढ़ से तो बच गए, लेकिन उनका सबकुछ बर्बाद हो गया। मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने के कारण उनका बाहरी दुनिया से संपर्क भी टूट गया। 10 दिन पहले नाजिरा कस्बे से प्रशासन ने नाव की मदद से उन्हें बचाया। सेवानिवृत्त प्रोफेसर मुकुल बेजबरुआ और उनकी पत्नी के पास अब केवल बदन पर पहने कपड़े ही बचे हैं। उनका घर कीचड़ और मलबे से भर गया है तथा उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

शिवसागर की ओएनजीसी कॉलोनी में रहने वाली मधुस्मिता बोरठाकुर का अनुभव भी कम डरावना नहीं था। वह और उनकी दो बेटियां कॉलोनी में बहुत तेजी से पानी भर जाने के कारण बाढ़ में फंसते-फंसते बचीं। उनके पति फील्ड ड्यूटी पर बाहर गए हुए थे। ऐसे में वह अपनी दोनों बेटियों के साथ एक खुली वैन में बैठकर वहां से निकलने में सफल रहीं और अगले कुछ दिन अपनी एक मित्र के घर बिताए। असम में एक सप्ताह से अधिक समय पहले आई इस बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही शिवसागर जिले में मचाई। इस साल राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 68 हो गई और छह लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। बेजबरुआ दंपति ने 19 जुलाई की रात भयावह मंजर का मुश्किल से सामना किया।

मुकुल बेजबरुआ ने कहा, ''रात करीब आठ बजे तेजी से बहते पानी की आवाज सुनाई दी। बाहर अफरा-तफरी मची हुई थी। मैं और मेरी पत्नी लकड़ी के एक पुराने दीवान पर चढ़ गए, जिसमें पुराने रजाई-कंबल रखे थे। अंदर रखा सामान पूरी तरह भीग गया था, लेकिन दीवान पानी में तैर रहा था और हम उसी पर बैठे रहे।'' उन्होंने कहा, ''पानी का बहाव इतना तेज था कि फ्रिज और अलमारी तक गिर गईं। कुछ भी नहीं बचा। हमने किसी तरह अपनी जान बचाई। बीस जुलाई की सुबह प्रशासन ने नाव की मदद से उन्हें बचाया। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो वे घर लौटे, लेकिन देखा कि उनका लगभग पूरा सामान नष्ट हो चुका था। उनके घर से दो ट्रक कीचड़ और मलबा निकाला गया। इसके बाद भी दो से तीन इंच तक गाद जमी हुई थी।

गड़गांव कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर मुकुल बेजबरुआ ने बताया कि वह 1992 से नाजिरा में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहां कभी इतनी भयानक बाढ़ नहीं देखी और न ही इसके बारे में सुना था। उन्होंने कहा, पहले भारी बारिश के बाद पानी भर जाता था, लेकिन ऐसी बाढ़ की कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने नुकसान पर दुख जताते हुए उन्होंने बाढ़ से प्रभावित अन्य लोगों की भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, ''मेरे पास किसी तरह जीवन दोबारा शुरू करने के कुछ साधन हैं। मेरा बेटा भी आ गया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रोजगार तक खो दिया है और अब भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं।'' उन्होंने प्रभावित लोगों के जल्द पुनर्वास की मांग की।

ओएनजीसी कॉलोनी में मधुस्मिता बोरठाकुर ने भी ऐसा ही मुश्किल समय देखा, जैसा पहले कभी नहीं देखा था। पानी का बहाव बढ़ता गया, वह अपनी नौ साल और तीन साल की दो बेटियों के साथ घर में फंसी रहीं। उन्होंने कहा, ''मेरे पति फील्ड ड्यूटी पर थे और एक सप्ताह बाद लौटने वाले थे। हम फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। किसी भी आपात स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं बहुत डर गई थी।'' आखिरकार उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के साथ एक खुली वैन में जगह बनाई और वहां से निकलकर अपनी एक मित्र के घर चली गईं। संयोग से वह इलाका बाढ़ से बच गया। हालांकि, बाढ़ का पानी अब उतर रहा है, लेकिन प्रभावित लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उनके लिए आपदा का पहला दौर भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन अब घरों से मलबा हटाना, उन्हें फिर से बसाना और इस दर्दनाक अनुभव से उबरना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

# शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के बाद ओडिशा पहुंचने पर प्रधान का भाजपा नेताओं ने जबर्दस्त स्वागत किया

**प्रधान के समर्थन उन्हें एक नायक के तौर पर पेश कर रहे हैं क्योंकि वह नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले ऐसे मंत्री हैं, जिन्होंने नैतिक आधार पर छोड़ा है पद**

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**भुवनेश्वर/भाषा।** विद्यार्थियों और युवाओं के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचने पर मंगलवार को भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान का ओडिशा के मंत्रियों और पार्टी विधायकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पांच मंत्रियों, 21 अन्य भाजपा विधायकों, दो पूर्व विधायकों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने यहां बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संबलपुर के सांसद प्रधान का स्वागत किया।

उनके समर्थकों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर अपने नेता का स्वागत किया और धर्मेंद्र प्रधान 'जिंदाबाद' के नारे लगाये। प्रधान ने तीन मई को नीट-यूजी परीक्षा में हुई अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ दिया। प्रधान के समर्थक उन्हें 'एक नायक' के तौर पर पेश कर रहे हैं क्योंकि वह नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले ऐसे मंत्री हैं, जिन्होंने 'नैतिक आधार' पर पद छोड़ा है।

एक राजनीतिक प्रेक्षक ने कहा, ''उन्यासी विधायकों में से 26 विधायक प्रधान का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इससे पार्टी के विधायकों के बीच उनकी स्वीकार्यता का पता चलता है। इन 26 विधायकों में पांच मंत्री भी हैं।''

हालांकि, ''दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, प्रधान ने न तो नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है और न ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बर्खास्त किया है। उन्हें देश के विद्यार्थियों और युवाओं के दबाव में अपना इस्तीफा देना पड़ा।'' मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल समेत प्रदेश भाजपा के विभिन्न नेताओं ने नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर एक मिसाल कायम करने वाला कदम उठाने' को लेकर प्रधान की तारीफ़ की है।

# पीडीपी अनुच्छेद-370 को बहाल करने की मांग को लेकर पांच अगस्त को प्रदर्शन करेगी : महबूबा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**श्रीनगर/भाषा।** पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली और कश्मीर मुद्दे के समाधान' की मांग को लेकर पांच अगस्त को पूरे जम्मू-कश्मीर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेगी।

केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने पीडीपी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, यहां मौजूद हमारे सभी लोग पांच अगस्त को अपने-अपने जिलों में अनुच्छेद 370 और 35ए को बहाल करने और कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ''पांच अगस्त वह दिन था जब हमसे सब कुछ छीन लिया गया''।

उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें ''कश्मीर मुद्दे के समाधान'' से संबंधित विषय भी शामिल है। पीडीपी के प्रस्ताव में कहा गया, ''पार्टी इस बात को लेकर अपना संकल्प दोहराती है कि सभी संबंधित पक्षों के बीच बातचीत, सुलह, भरोसा बढ़ाने और सार्थक लोकतांत्रिक भागीदारी के जरिए शांति ही एकमात्र रास्ता है।''

# आंध्र प्रदेश में पिछले एक महीने में कोविड-19 के दो मामले : नड्डा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को बताया कि आंध्र प्रदेश में पिछले एक महीने में कोविड-19 के दो मामले सामने आए हैं और कडप्पा जिले के नमूनों की जीनोम अनुक्रमण जांच में ओमिक्रॉन के आरएफ.5 स्वरूप की पुष्टि हुई है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चिंता वाले स्वरूप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है।

नड्डा ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 24 जून से 26 जुलाई, 2026 के बीच कोविड-19 के 12 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कडप्पा जिले में कोविड-19 से तीन मौतें दर्ज की गईं। इन सभी मरीजों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की पुरानी बीमारी और लंबे समय से शराब सेवन जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याएं थीं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) द्वारा की गई जीनोम अनुक्रमण जांच में कडप्पा जिले से मिले कोविड-19 संक्रमित नमूनों में सार्स-कोव-2 के ओमिक्रॉन स्वरूप के आरएफ.5 स्वरूप का अधिक प्रसार पाया गया। उन्होंने कहा, ''इस स्वरूप को डब्ल्यूएचओ ने चिंता वाले स्वरूप (वीओसी), रुचि वाले स्वरूप (वीओआई) या निगरानी वाले स्वरूप (वीयूएम) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है।'' नड्डा ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम-एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईडीएसपी-आईएचआईपी) के माध्यम से कोविड-19 समेत इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और गंभीर श्वसन संक्रमण (एसएआरआई) पर लगातार करीबी निगरानी रख रहा है।

# मुंबई जा रही महालक्ष्मी एक्सप्रेस के डिब्बे में धुआं निकलने से हड़कंप, कोई हताहत नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**ठाणे/भाषा।** कोल्हापुर से मुंबई जा रही महालक्ष्मी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कर्जत के पास मंगलवार सुबह धुआं निकलने से यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर कर्जत के मंकी हिल खंड में हुई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अनुसार, धुआं संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण उठा था। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत प्रभावित डिब्बे की जांच की जिसके बाद ट्रेन आगे की यात्रा के लिए रवाना हुई।

कर्जत जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किरण मटकर ने कहा, ''इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।'' अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रेन के कर्जत स्टेशन से जाने का समय सुबह पांच बजकर 30 मिनट है, लेकिन इस घटना के कारण इसके रवाना होने में देरी हुई। अधिकारियों द्वारा डिब्बे की जांच और आवश्यक कार्रवाई किए जाने के बाद ट्रेन सुबह छह बजकर 15 मिनट पर रवाना हुई।

# दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने यात्री से सोने से भरे तीन कैप्सूल बरामद किए

**नई दिल्ली/भाषा।** दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने जकार्ता से आए एक यात्री को रोककर उसके कब्जे से तीन कैप्सूल बरामद किए, जिनमें 744 ग्राम सोना होने का संदेह है। यात्री ने स्वीकार किया कि उसने इन कैप्सूल को निगल रखा था। आधिकारिक बयान के अनुसार, सोमवार को यहां पहुंचे इस यात्री को अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) प्रोफाइलिंग के आधार पर ग्रीन चैनल से बाहर निकलने के बाद रोका गया।

बयान में कहा गया कि यात्री के सामान की एक्स-रे जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हालांकि, यात्री का व्यवहार संदिग्ध प्रतीत होने परअधिकारी उसे विस्तृत पूछताछ के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) के कार्यालय ले गए। बयान में कहा गया, लगातार पूछताछ के दौरान यात्री ने स्वीकार किया कि उसने कुल 744 ग्राम वजन के सोने के तीन ठोस टुकड़े निगल रखे थे।

# तेलुगु फिल्मों की 'अभिनेत्री पावला' श्यामला का 75 वर्ष की आयु में निधन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**हैदराबाद/भाषा।** तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री 'पावला' श्यामला का मंगलवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 75 वर्ष की थीं।

अस्पताल सूत्रों ने बताया कि उम्र संबंधी बीमारियों का उस्मानिया सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहीं श्यामला को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया।

मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (एमएए) की संयुक्त सचिव कराटे' कल्याणी ने पीटीआई-भाषा' को बताया कि श्यामला का अंतिम संस्कार 29 जुलाई को हैदराबाद में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एमएए की ओर से की जाएंगी। चार दशक से अधिक लंबे फिल्मी करियर में श्यामला ने अनेक तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। वर्ष 1980 के शुरुआती दशक में इसी नाम के एक चर्चित नाटक में उनके अभिनय के बाद उन्हें लोकप्रिय रूप से 'पावला' श्यामला के नाम से जाना जाने लगा। दिग्गज फिल्मकार और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित के. विश्वनाथ के निर्देशन में बनी 'स्वर्ण कमलम' तथा कृष्ण वामसी की 'खड्गम' में उनके अभिनय को विशेष सराहना मिली और इन्हीं फिल्मों से उन्हें व्यापक पहचान हासिल हुई। पिछले कुछ वर्षों से श्यामला स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ-साथ आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना कर रही थीं।

# अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर एआईबी की अंतिम मसौदा रिपोर्ट अक्टूबर में दायर की जाएगी : सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय बताया कि जून, 2025 में अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया उड़ान हादसे की जांच करने वाले विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की अंतिम मसौदा रिपोर्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश की जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों पर भी संज्ञान लिया कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स' एएआईबी को अपने सुझाव दे सकता है, जिन पर एएआईबी जांच के दौरान आवश्यक समझे जाने पर विचार किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि याचिकाकर्ताओं में से एक द्वारा दायर आवेदन में किए गए अनुरोध पर चार 'सिमुलेशन' परीक्षण किए जा चुके हैं।

विधि अधिकारी ने कहा कि अंतिम मसौदा रिपोर्ट पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी।

अदालत एक एनजीओ, एक विधि छात्र और मृत पायलट के पिता द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में दुर्घटना की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी। एएआईबी ने हाल में उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जांच की अंतिम मसौदा रिपोर्ट इस साल अक्टूबर तक तैयार होने की संभावना है।

बारह जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एआई-171 (बोइंग 787-8) उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 260 लोगों की मौत हो गई थी।

# पति-पत्नी दोनों को घर व बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहिए : उच्च न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**मुंबई।** मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि समानता का दावा चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता और यदि पति एवं पत्नी दोनों कमाते हैं तो घर चलाने और बच्चे की शिक्षा का खर्च दोनों को मिलकर उठाना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी अलग रह रही पत्नी और नाबालिग बेटे के लिए तय मासिक भरण-पोषण राशि कम करते हुए की। न्यायमूर्ति एम. एम. साथये की एकल पीठ ने पिछले सप्ताह दिए आदेश में पारिवारिक अदालत के जनवरी 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पति को पत्नी और बेटे के लिए प्रति माह 50,000 रुपये भरण-पोषण खर्च देने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह राशि घटाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी।

अदालत ने कहा कि पति मुंबई के अंधेरी स्थित उस मकान की ईएमआई चुका रहा है, जिसमें पत्नी और बेटा रह रहे हैं, जबकि नवी मुंबई के पनवेल स्थित दूसरे मकान की ईएमआई भी वही भर रहा है। वहीं, वह स्वयं बिहार में रह रहा है। अदालत ने कहा कि पत्नी इन दोनों मकानों की ईएमआई में

कोई योगदान नहीं दे रही है। पति ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि मासिक भरण-पोषण की राशि 50,000 रुपये से घटाकर 25,000 रुपये की जाए। उसने पत्नी से बिहार में उसके साथ रहने या कम से कम पनवेल स्थित मकान में रहने का अनुरोध किया था, ताकि वह अंधेरी वाला मकान बेचकर अपना आर्थिक बोझ कम कर सके, लेकिन पत्नी ने इससे इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि पति की इस मांग में कोई अनुचित बात नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि पत्नी बिना ईएमआई चुकाए या उसमें आर्थिक योगदान दिए अंधेरी जैसे महंगे इलाके में रहने की सुविधा चाहती है, तो ऐसे में पति द्वारा पूरे ईएमआई का भुगतान करते हुए भरण-पोषण की राशि कम करने की मांग करना गलत नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा, समानता का दावा चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब दोनों पक्ष कमाने वाले हों।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि पति और पत्नी दोनों कमाते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा मिले, तो उसकी पढ़ाई का खर्च भी दोनों को मिलकर उठाना चाहिए। पति ने अदालत को बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान उसकी नौकरी चली गई थी और अब वह पहले की तुलना में कम वेतन वाली नौकरी कर रहा है, जिससे वह आर्थिक दबाव में है। अदालत ने कहा कि कोविड-19 महामारी का असर अनेक लोगों के रोजगार और कारोबार पर पड़ा था, इसलिए पति की आय में कमी आने का उचित कारण मौजूद है।

# मेकेदातु पर जल शक्ति मंत्री का संसद में दिया गया जवाब वापस लिया जाए : विजय का मोदी से आग्रह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई।** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के संबंध में राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से दिया गया यह जवाब ''निराशाजनक'' है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में कर्नाटक के लिए तटवर्ती राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य नहीं बताया गया है।

मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में आग्रह किया कि जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा 27 जुलाई, 2026 को राज्यसभा में (अतारांकित प्रश्न संख्या 876 के) उत्तर में अंतरराज्यीय जल विवादों से जुड़े स्थापित कानूनों और कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख किए बिना दिया गया जवाब वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक-आंध्र प्रदेश आलमट्टी मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी परियोजना के लिए निचले तटवर्ती राज्य की सहमति पूरी तरह आवश्यक है।

विजय ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मेकेदातु बांध परियोजना को तब तक कोई वैधानिक या प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी जाए, जब तक वह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के फैसले और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ना हो। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि मंत्री ने संसद के ऊपरी सदन में कहा कि कावेरी जल विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.02.2018 के निर्णय के अनुसार, कर्नाटक राज्य को कावेरी नदी पर किसी भी प्रकार की संरचना के निर्माण के लिए अन्य तटीय राज्यों की सहमति प्राप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।

विजय ने कहा, जल शक्ति राज्य मंत्री का यह निराशाजनक जवाब निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति से जुड़ी मौजूदा कानूनी व्यवस्थाओं और स्थापित कानून को ध्यान में रखे बिना दिया गया प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले के खंड-18 को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि इस खंड में प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र के भीतर जल के नियमन का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह केवल उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है जो न्यायाधिकरण के आदेश के विपरीत ना हो। उन्होंने कहा कि इस प्रकार ऐसी किसी भी परियोजना, जिससे न्यायाधिकरण के फैसले के तहत निर्धारित जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, उसकी समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वह फैसले के अनुरूप है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायाधिकरण ने स्वयं कई महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए हैं। उन्होंने कहा कि केरल की पंबर जलविद्युत परियोजना के मामले में, जिसमें केवल 0.1 टीएमसी जल उपयोग शामिल था, न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया था कि केरल और तमिलनाडु संयुक्त रूप से जल छोड़ने की समय-सारणी तय करें ताकि निचले क्षेत्रों की सिंचाई प्रतिकूल तौर पर प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि न्यायाधिकरण ने केवल वार्षिक जल मात्रा को ही नहीं, बल्कि निचले तटवर्ती राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाले जल प्रवाह के समन्वित नियमन को भी अत्यधिक महत्व दिया था।

विजय ने कहा कि फैसले का खंड-11 विशेष रूप से किसी ऊपरी तटवर्ती राज्य को ऐसी कार्रवाई करने से रोकता है, जिससे निचले राज्यों को निर्धारित जल आपूर्ति प्रभावित हो, जब तक कि नियामक प्राधिकार के साथ आपसी सहमति और परामर्श ना हो। उन्होंने कहा कि खंड-20 में भी यह माना गया है कि न्यायाधिकरण के फैसले में बदलाव केवल संबंधित राज्यों के बीच सहमति से ही किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु का स्पष्ट मत है कि प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना को केवल एक इंजीनियरिंग परियोजना के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि इसकी कानूनी वैधता की पहले कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले और 16 फरवरी 2018 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में पड़ताल की जानी चाहिए।

# मेकेदातु बांध पर केंद्रीय मंत्री के जवाब ने न्यायालय के फैसले की गलत व्याख्या की : पलानीस्वामी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई।** ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर मेकेदातु में प्रस्तावित बांध को लेकर संसद में केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी के जवाब की मंगलवार को आलोचना की और कहा कि जवाब में उच्चतम न्यायालय के फैसले की गलत व्याख्या की गई है।

पलानीस्वामी ने केंद्रीय मंत्री के उक्त बयान पर गहरा आश्चर्य जताते हुए कहा कि अंतरराज्यीय नदियां राष्ट्रीय संपत्ति हैं और ऊपरी तटवर्ती राज्य एकतरफा तरीके से जल प्रवाह में बदलाव नहीं कर सकते। उन्होंने केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों से आग्रह किया कि वे लोगों की भावनाओं से जुड़े मुद्दों, खासकर मेकेदातु बांध जैसे विषयों पर अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय जल विवादों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दिए जाने वाले जवाबों में ऐतिहासिक संदर्भ, कानूनी तथ्यों और प्रभावित लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने 2018 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के पृष्ठ 342 का हवाला दिया और उनके अनुसार, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित कोई भी राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, जिससे निचले हिस्से में स्थित राज्यों को निर्धारित जल वितरण प्रभावित हो। यह विवाद केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी द्वारा सोमवार को राज्यसभा में पीएमके सांसद अंबुमणि रामदास के एक सवाल के लिखित जवाब में यह कहने के बाद शुरू हुआ कि कावेरी जल विवाद मामले में

उच्चतम न्यायालय के 16 फरवरी 2018 के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि कर्नाटक को कावेरी नदी पर कोई ढांचा बनाने से पहले तमिलनाडु, केरल या पुडुचेरी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के 2018 के फैसले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत कावेरी नदी पर ढांचा बनाने से पहले कर्नाटक के लिए निचले तटवर्ती राज्यों से मंजूरी लेना अनिवार्य हो। मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि कावेरी नदी तमिलनाडु के 20 जिलों में पेयजल का प्रमुख स्रोत है और राज्य के उपजाऊ कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कृषि की जीवनरेखा भी है। उन्होंने आरोप लगाया, कर्नाटक इस साल पहले ही तमिलनाडु को निर्धारित हिस्से का पानी समय पर जारी करने में विफल रहा है, जिससे कुरुवई धान की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है और कई क्षेत्रों में पेयजल संकट पैदा हुआ है।''

पलानीस्वामी ने कहा कि कर्नाटक द्वारा मेकेदातु में जलाशय बनाने का कदम निचले क्षेत्रों में जल सुरक्षा को और खतरे में डाल देगा। उन्होंने अन्नाद्रमुक सरकारों के लगातार प्रयासों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इन्हीं प्रयासों के कारण एक जून 2018 को कावेरी कार्यान्वयन योजना को राजपत्र में अधिसूचित किया गया और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) का गठन भी हुआ। पलानीस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 201% और 2018 के बीच कई बार प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखकर तथा मुलाकात करके मेकेदातु बांध प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के नदी संबंधी अधिकारों को प्रभावित करने वाली किसी भी कार्रवाई पर अन्नाद्रमुक चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा, कावेरी नदी तमिलनाडु की जीवनरेखा है। वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया है। ऐसे में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दिया गया जवाब तमिलनाडु के लोगों को स्तब्ध करने वाला है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवालों का जवाब देते समय संबंधित राज्य के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

# तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कार्यालय नामक्कल कविग्नर मालिगई में स्थानांतरित किया जाएगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई।** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का कार्यालय जल्द ही सचिवालय परिसर स्थित नामक्कल कविग्नर मालिगई भवन की 10वीं मंजिल पर स्थानांतरित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, नया कार्यालय अधिक विशाल है और यहां से बंगाल की खाड़ी का विस्तृत दृश्य दिखाई देता है। मुख्यमंत्री अब तक ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित कार्यालय से कामकाज कर रहे थे। हालांकि, जगह की कमी और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को आधुनिक भवन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्य सचिव एम. साई कुमार के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने 10वीं मंजिल को मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मंजिल पर मौजूद सूचना एवं तमिल विकास, पर्यटन, गृह और वाणिज्यिक कर विभागों को चेपक स्थित कलैवनार अरंगम और भवन की अन्य मंजिलों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। छब्बीस जुलाई से 10वीं मंजिल पर आंतरिक मरम्मत, ढांचागत बदलाव और अन्य निर्माण कार्य जारी हैं। तैयार होने के बाद यह हिस्सा उच्च सुरक्षा क्षेत्र होगा, जहां मुख्यमंत्री, उनके सलाहकार और चार सचिव बैठेंगे।

सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री का दैनिक कामकाज नए कार्यालय से होगा, लेकिन विशेष सरकारी कार्यक्रमों के लिए वह फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित अपने ऐतिहासिक कक्ष का उपयोग करते रहेंगे। करीब छह दशक बाद यह पहली बार होगा जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नियमित कार्यालय फोर्ट सेंट जॉर्ज से बाहर संचालित होगा।

इससे पहले 2010-11 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने कुछ समय के लिए ओमंदूरार गवर्नमेंट एस्टेट स्थित सचिवालय से कामकाज किया था। हालांकि, 2011 में सत्ता में लौटने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने सचिवालय को फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थानांतरित कर दिया था।

# किसानों के विरोध के बावजूद कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे विजय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई।** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद के हल के लिए पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के पक्ष में हैं, हालांकि किसान संगठनों ने सरकार से प्रस्तावित वार्ता को रद्द करने की मांग की है। एक आधिकारिक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

राज्य में, विशेषकर कावेरी डेल्टा के तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जिलों में भीषण जल संकट है। इससे अल्पावधि की कुरुवई धान की फसल प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, जलाशय में पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण परंपरागत रूप से 12 जून को मेट्टूर बांध को खोले जाने का कार्यक्रम भी टालना पड़ा। ऐसे में किसानों ने राज्य सरकार से कर्नाटक के साथ बातचीत करने के बजाय कानूनी विकल्प तलाशने की मांग की है।

सोमवार को राज्य के कृषि मंत्री आर. विनोथ के साथ हुई परामर्श बैठक में शामिल किसान प्रतिनिधियों ने दोनों राज्यों के बीच प्रस्तावित वार्ता रद्द करने की मांग की। तमिलनाडु कावेरी किसान संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रत्यक्ष बातचीत स्थापित कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करेगी और उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत होगी। वहीं, विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमक), जिसने द्विपक्षीय वार्ता का कड़ा विरोध किया है, उसने राज्य सरकार से कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए एक विशेष अधिकरण गठित कराने और तमिलनाडु को उसके हिस्से का कावेरी जल दिलाने के लिए प्रयास करने की मांग की है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने 2018 के ऐतिहासिक फैसले में कावेरी जल बंटवारे के क्रियान्वयन और उसकी निगरानी के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन किया था। एक जून से 22 जुलाई, 2026 के बीच तमिलनाडु को 31 टीएमसी फुट (31 अरब घन फुट) पानी मिलना चाहिए था, लेकिन उसे केवल 3.5 टीएमसी फुट पानी ही प्राप्त हुआ।

# नीट परीक्षा पर रोक लगनी चाहिए : द्रमुक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई/नई दिल्ली।** चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को अनावश्यक बताते हुए द्रमुक ने मंगलवार को कहा कि इस परीक्षा रोक लगनी चाहिए क्योंकि इसमें एकरूपता नहीं है। लोकसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा में भाग लेते हुए द्रविण मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा, ''यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं।'' मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान ही नहीं कर रही है और मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है।

उन्होंने कहा, ''नीट में एकरूपता नहीं है। यह छात्रों के लिए नहीं है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।'' मारन ने कहा, ''अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए। इसे रोकिए।'' उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। द्रमुक सांसद ने कहा, ''हम कह रहे हैं कि हमें नीट नहीं चाहिए। आप अड़े क्यों हैं। आप गलती कर रहे हैं। यह परीक्षा हमारे युवाओं और बच्चों के खिलाफ है।''

# चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस का पहली तिमाही में मुनाफा 46% बढ़कर 1,656 करोड़ रु.

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई/नई दिल्ली।** मुरुगप्पा समूह की वित्तीय सेवा कंपनी चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 46 प्रतिशत बढ़कर 1,656 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में कंपनी ने 1,138 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अप्रैल-जून अवधि में उसकी कुल आय 22 प्रतिशत बढ़कर 8,957 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले इसी अवधि में 7,353 करोड़ रुपये थी।

जून के अंत तक कंपनी के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 2.54 लाख करोड़ रुपये हो गईं जो एक साल पहले 2.07 लाख करोड़ रुपये थीं। समीक्षाधीन तिमाही में ऋण वितरण 22 प्रतिशत बढ़कर 29,612 करोड़ रुपये हो गया जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 24,325 करोड़ रुपये था। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की परिसंपत्ति गुणवत्ता कमजोर हुई। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 4.29 प्रतिशत थीं। शुद्ध एनपीए भी बढ़कर 2.95 प्रतिशत हो गया जो एक साल पहले 2.86 प्रतिशत था। इस बीच, एनबीएफसी के निदेशक मंडल ने निजी नियोजन के आधार पर एक या अधिक किस्तों में 55,000 करोड़ रुपये तक के गारंटी वाले /या बिना गारंटी वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर धन जुटाने को मंजूरी दे दी है।

# तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनाव 2027 की शुरुआत तक टाले जाने की संभावना

**चेन्नई।** तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनाव अगले साल की शुरुआत तक टल सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने सातवें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल इस साल दिसंबर के अंत तक बढ़ा दिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वितरण तय करने के लिए नगर निकाय चुनाव सातवें राज्य वित्त आयोग से जुड़े हैं और बजट आवंटन सहित स्थानीय निकाय चुनावों की जरूरी तैयारियां भी इसी आकलन पर निर्भर करती हैं।

राज्य सरकार ने हाल में एक आदेश जारी कर आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। पहले इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2026 को समाप्त होना था। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव 2027 की शुरुआत में कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। पिछले स्थानीय निकाय चुनाव 19 फरवरी, 2022 को एक ही चरण में नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए कराये गये थे।

**उत्तर पश्चिम रेलवे**
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
पत्र सं.-WB-74-W-O/Works/NIT/X
दिनांक: 22.07.2026

मंडल रेल प्रबन्धक, इंजीनियरिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है- ई-निविदा सूचना सं०:- 111 of 2026-27, कार्य का नाम व स्थान:- Provision of S&T centralized monitoring control building with arrangements for unified NMS of KAVACH, EI networking, centralized exchange- VOIP and IP-MPLS, NMS, RDPMS, CCTV etc. and Improvement of DRM office building at Jodhpur DRM Office., अनुमानित लागत रूपये:- 82963162.38, बयाने की राशि रुपये:- 1659300.00, ई-निविदा सूचना सं०:- 112 of 2026-27, कार्य का नाम व स्थान:- Construction of RCC box culvert bridge at km 151/0-2,155/9-156/1, 152/4-5, 153/0-1,99/9-100/0, 154/5-6, 186/4-9 and pitching and other protection work in RKB-JSM section. अनुमानित लागत रूपये:- 48743639.36, बयाने की राशि रुपये:- 974900.00, ई-निविदा सूचना सं०:- 113 of 2026-27, कार्य का नाम व स्थान:- Supplying, stacking & Loading of Railway ballast in to ballast hoppers at Pipar Road Jn ballast depot of Jodhpur Division under ADEN/LINE / JODHPUR, अनुमानित लागत रूपये:- 55425000.00, बयाने की राशि रुपये:- 1108500.00 निविदा सूचना संख्या 111 of 2026-27 निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 11.08.2026 को, 112 of 2026-27 निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 12.08.2026 को, 113 of 2026-27 निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 17.08.2026 को 15:00 बजे तक है। वेबसाईट का विवरण जहाँ पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती है www.ireps.gov.in

1085-DO/26

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

# अशोक लेलैंड ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए वित्त पोषण सुविधा देने को यूको बैंक से साझेदारी की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

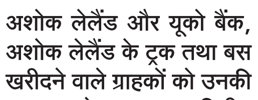

**चेन्नई/नई दिल्ली।** हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने अपने ट्रक और बसों के खरीदारों को वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूको बैंक के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अशोक लेलैंड और यूको बैंक, अशोक लेलैंड के ट्रक तथा बस खरीदने वाले ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुरूप वित्तीय समाधान उपलब्ध कराएंगे।

अशोक लेलैंड के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के. एम. बालाजी ने कहा, यह रणनीतिक साझेदारी हमारे वाणिज्यिक वाहनों की श्रृंखला को देशभर के कारोबारों के लिए अधिक सुलभ बनाकर बाजार में हमारी मौजूदगी को और मजबूत करेगी। यूको बैंक के उप महाप्रबंधक आर. एस. अजित ने कहा, ''यह साझेदारी कारोबारों को आसान तथा उनकी जरूरतों के अनुरूप वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। इससे वाहन खरीदना आसान होगा और वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।''

# तमिलनाडु में मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में समिति गठित, राजस्व बढ़ाने के उपाय सुझाएगी

**चेन्नई/भाषा।** तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कर और गैर-कर राजस्व में वृद्धि के उपाय सुझाने के लिए अर्थशास्त्री एवं योजना आयोग (अब नीति आयोग) के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक राजस्व वृद्धि समिति का गठन किया है। सरकार ने बताया कि यह उच्च स्तरीय समिति अनुपालन में सुधार लाने, कर चोरी रोकने, दरों, शुल्क और छूट को तर्कसंगत बनाने तथा नए स्रोतों की पहचान करने पर ध्यान देगी। अधिकारी ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार कर चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत यह कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य अहलूवालिया इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में सदस्य के रूप में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थशास्त्र के चेयर प्रोफेसर के पी कृष्णन, कर नीति विशेषज्ञ अरबिंद मोदी, सीबीईसी के पूर्व चेयरमैन नजीब शाह, तमिलनाडु वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एम ए सिद्दीकी, और मद्रास इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, चेन्नई के निदेशक एम सुरेश बाबू शामिल होंगे।

# कोडैकनाल में पानी का भारी संकट, लंबे समय तक बारिश न होने से जलाशय खाली

**डिंडीगुल।** तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक, कोडाइकनाल, पीने के पानी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। लंबे समय तक सूखे मौसम और कम बारिश के कारण पूरे शहर में पानी की उपलब्धता में भारी कमी आई है। पानी की बढ़ती किल्लत से स्थानीय लोग, बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर परेशान हैं। म्युनिसिपल वॉटर सप्लाई अब कई घरों में सात से आठ दिनों में सिर्फ एक बार पहुंच रही है।

पहाड़ी इलाके के इस शहर में 24 म्युनिसिपल वार्डों में लगभग 46,000 लोग रहते हैं और यहां साल भर पर्यटकों की भी भारी आवाजाही रहती है। आम दिनों में कोडाइकनाल में लगभग 5,000 से 6,000 पर्यटक आते हैं जबकि वीकेंड और छुट्टियों में यह संख्या 20,000 से भी अधिक हो जाती है। बढ़ती मांग ने पहले से ही कम हो रहे जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी म्युनिसिपैलिटी पानी की सप्लाई करती है, तो उन्हें पानी जमा करके रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगली सप्लाई शायद एक सप्ताह तक न आए। कई कमर्शियल प्रतिष्ठानों ने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइवेट वॉटर टैंकर खरीदना शुरू कर दिया है।

**दक्षिण पश्चिम रेलवे**
ई-निविदा सूचना सं. 16 UBL 2026-27, दिनांक: 21.07.2026
भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार ई-नीलामी / ई-निविदा हेतु निविदादाताओं को आमंत्रित करते हैं:

| क्र.सं. | विवरण संक्षेप में | अनुमानित लागत |
| --- | --- | --- |
| 1 | **हुबली विभाग:** सहायक मंडलीय इंजीनियर / बेलगावी (बीजीएम) उप मंडल के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए यार्डों पर ट्रैक का रखरखाव कार्य। | रु. 3,77,34,243.00 |
| 2 | **हुबली विभाग:** सहायक मंडलीय इंजीनियर / बेलगावी (बीजीएम) उप मंडल के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए मिड सेक्शन पर ट्रैक का रखरखाव कार्य। | 3,73,56,293.00 |
| 3 | **हुबली विभाग:** सहायक मंडलीय इंजीनियर / बेलगावी (बीजीएम) क्षेत्राधिकार पर एलसी नं. 399, 415 और 420 पर एलसी गेट लॉड्जस का प्रस्तावित निर्माण कार्य और बोरवेल का व्यवस्था, एप्रोच रोड का मरम्मत, पेंटिंग, रूफ शीटिंग, शौचालय सुविधाएं आदी., का प्रावधान से एलसी गेटों का सुधारण कार्य। | रु. 1,48,91,115.00 |
| 4 | **हुबली विभाग:** सहायक मंडलीय इंजीनियर / बेलगावी (बीजीएम) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए ट्रैक कार्यों के लिए लूब्रिकेशन। | रु. 88,07,633.00 |
| 5 | **हुबली विभाग: उप कार्य-1: लोंडा - वास्को-ड-गामा (एलडी-वीएसजी) खंड:** लोंडा - तिनाईघाट (एलडी-टीजीटी) स्टेशनों के बीच किमी. 10/200-300 पर एलसी नं. 06 के बदले क्रमानुसार बॉक्स पुशिंग विधि अनुसार आरयूबी ना निर्माण कार्य। **उप कार्य-2: लोंडा - वास्को-ड-गामा (एलडी-वीएसजी) खंड:** लोंडा - तिनाईघाट (एलडी-टीजीटी) स्टेशनों के बीच किमी. 12/0-100 पर एलसी नं. 07 के बदले क्रमानुसार बॉक्स पुशिंग विधि अनुसार आरयूबी ना निर्माण कार्य। (दो पैकेट व्यवस्था) | रु. 11,43,66,812.00 |
| 6 | **हुबली विभाग:** वरिष्ठ मंडलीय इंजीनियर / पचिम / हुबली (यूबीएल) क्षेत्राधिकार में एटी वेल्ड का आपूर्ती। | रु. 93,56,398.00 |
| 7 | **हुबली विभाग:** वास्को-ड-गामा पर समुदाय भवन में रूफिंग, दरवाज़े और खिड़कियाँ, फ्लोरिंग, शौचालय आदी., का सुधारण कार्य। | रु. 33,25,070.00 |

निविदाओं जमा करने की अंतिम तिथि: 18.08.2026, 11:00 बजे तक
विवरण के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in में
वरिष्ठ विभागीय इंजीनियर / समन्वय / हुबली
PUB/325/AAMG/PRB/SWR/2026-27
आसान टिकट बुकिंग, PNR स्थिति और दूसरी रेलवे सेवाओं के लिए RailOne ऐप डाउनलोड करें।
South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRAILWAYHQ | sw_railways

# युवाओं के हर सपने को पूरा कर रही डबल इंजन सरकार : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा से लेकर खेल, रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक युवाओं के हर सपने को पूरा करने में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार पेपरलीक पर प्रभावी रोक, रिकॉर्ड सरकारी भर्तियों, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन तथा कौशल विकास के माध्यम से युवाओं का उज्ज्वल भविष्य बनाने में सहयोगी बन रही है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित 'सपनों की उड़ान' कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विचारशील, अनुशासित एवं संस्कारवान युवा विकसित भारत-विकसित राजस्थान के आधार हैं। युवा नए विचार और नई ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारी सरकार युवाओं से संवाद कर बजट में उनके बहुमूल्य सुझावों को शामिल करती है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों को और बेहतर बनाने के लिए युवाओं के साथ इस तरह के संवाद बेहद महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार युवाओं के सुझावों पर विचार कर आगामी योजनाएं तैयार कर रही है।

उन्होंने कहा कि माता-पिता बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं, युवा उनसे सीख लेकर लगन, मेहनत, अनुशासन, संस्कारों को आत्मसात करें और आत्मविश्वास के साथ उनके सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा कि युवाओं का सामर्थ्य असीमित है। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुरूप हमारे प्रदेश का युवा विकास में अपना योगदान दे।

हर युवा को सम्मान मिले और उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत ढाई वर्षों में 1 लाख 78 हजार से अधिक युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को साकार किया है। करीब 51 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं तथा 80 हजार से अधिक पदों की भर्ती कलैण्डर में शामिल है। साथ ही, 70 हजार नए पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। वहीं, निजी क्षेत्र में भी साढ़े चार लाख रोजगार दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेपरलीक के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है, कानून को और सख्त बनाया गया है और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाया जा रहा है। पेपरलीक के अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एसआईटी का गठन कर पेपरलीक और अन्य अनियमितताओं के मामलों में 569 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारी सरकार द्वारा अब तक 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपरलीक के आयोजित की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का युवा केवल नौकरी लेने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने, इसके लिए सरकार द्वारा उद्यमिता एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत अब तक 4 हजार 623 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं तथा 1 हजार 62 स्टार्टअप्स को आई-स्टार्ट फंड से 34 करोड़ रुपये की फंडिग प्रदान की गई। 9 स्टार्टअप प्रोग्राम पूर्ण किए गए हैं, जिसमें कुल 988 स्टार्टअप्स ने भाग लिया। साथ ही, राज्य कौशल नीति-2025 और युवा नीति भी जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि अपने प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों के दम पर राजस्थान अब खेलों में नई पहचान बना रहा है। राज्य सरकार खेल संरचना का विस्तार, अकादमियों की स्थापना, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्थान टारगेट ऑलम्पिक पोडियम योजना लागू की गई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। साथ ही, 41 जिला मुख्यालयों पर आवासीय खेल अकादमियां भी प्रारंभ की गई हैं।

# चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में बरती जाए सख्ती: दिलावर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और चारागाह विकास समितियों का पुनर्गठन करने के निर्देश दिए। दिलावर ने मंगलवार को यहां आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की बजट घोषणाओं, स्वामित्व योजना तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समुदायों को आवासीय पट्टे वितरित करने की प्रगति की समीक्षा की गई। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य की नियमित निगरानी की जाए और प्रक्रियाधीन मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। दिलावर ने कहा कि सरकार की प्रत्येक बजट घोषणा आमजन से किया गया संकल्प है, इसलिए सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। मंत्री ने चारागाह भूमि पर बढ़ते अतिक्रमणों पर चिंता जताते हुए कहा कि चारागाह सार्वजनिक संपत्ति है और इसकी सुरक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में चिन्हित 200 बड़े अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज कर कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिलावर ने कहा कि कई स्थानों पर चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर चारागाह भूमि समाप्त हो जाएगी तो गौवंश के लिए चराई की व्यवस्था करना कठिन होगा।

मंत्री ने कानून के सभी प्रावधानों का उपयोग करते हुए चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और चारागाह विकास समितियों का पुनर्गठन करने के निर्देश दिए।

बैठक में मंत्री ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 प्रकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने पांच जिलों में जांच पूरी हो चुके मामलों में अयोग्य अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त करने और शेष मामलों को आगे की जांच के लिए विशेष कार्यबल (एसओजी) को भेजने के निर्देश दिए। दिलावर ने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों की सरकार हैं और उन्हें अधिक सक्षम, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से पंचायत स्तर पर सुशासन को और मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

# पुलिस अकादमी ने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने पुलिस कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राजस्थान पुलिस अकादमी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच यह समझौता पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक शर्मा ने कहा कि करीब 200 वर्ष पुराने इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ जुड़ना राजस्थान पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के अनुभव और उपलब्ध आंकड़ों तथा विश्वविद्यालय की शोध विशेषज्ञता के समन्वय से पुलिसिंग, पुलिस कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य व प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे।

शर्मा ने कहा कि इस साझेदारी से पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं और विशेषज्ञ व्याख्यानों का लाभ मिलेगा, जिससे तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य व पेशेवर दक्षता को भी मजबूती मिलेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रारंभिक चरण में सहयोग विश्वविद्यालय के 'स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज' के साथ किया जाएगा।

समझौते के तहत मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक देखभाल, स्वास्थ्य विज्ञान, पुलिस कल्याण और अन्य साझा विषयों पर संयुक्त शोध एवं अनुसंधान किए जाएंगे। डीजीपी शर्मा ने इस दौरान हाल के वर्षों में पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से इस विषय पर विशेष अध्ययन कर सुझाव देने का आग्रह किया।

समारोह में राजस्थान पुलिस अकादमी की ओर से अतिरिक्त निदेशक शंकरदत्त शर्मा तथा विश्वविद्यालय की ओर से प्रो. विमल कुमार शर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

# धौलपुर जिले में बीते ढाई साल में दो हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य किये गए : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कहा कि पिछले ढाई साल में धौलपुर जिले में लगभग 2,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य किये गए हैं। मुख्यमंत्री धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की फूलपुर ग्राम पंचायत में आयोजित लोकार्पण-शिलान्यास समारोह एवं जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार धौलपुर जिले के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी और पिछले ढाई साल में जिले में लगभग 2,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं। शर्मा ने कहा, हम जनता की सुनते हैं, इसलिए न तो काम की कमी है और न ही बजट की।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 177 करोड़ रुपये लागत के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता को पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि के अतिरिक्त तीन हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। शर्मा ने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है और 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सशक्त और समृद्ध बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, युवाओं सहित प्रत्येक वर्ग के सपनों को साकार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बेढम ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।

# राजस्थान में कई जगह भारी बारिश होने का पूर्वानुमान

जयपुर। राजस्थान के कई इलाकों में आज और कल एक नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। साथ ही अन्य मानसूनी परिस्थितियों के कारण आज मंगलवार से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 29 जुलाई से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर व बीकानेर संभाग के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इस दौरान दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी एवं अतिभारी बारिश हो सकती है। तीस जुलाई से दो अगस्त के दौरान भी पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून सक्रिय रहने तथा कहीं-कहीं भारी एवं अतिभारी बारिश होने का अनुमान है।

वहीं मंगलवार सुबह तक बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य में अनेक जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 67.0 मिलीमीटर (भारी वर्षा) वर्षा राश्मी (चित्तौड़गढ़) और आबू रोड (सिरोही) में हुई।

# राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह-2026 के सफल, गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि बीकानेर के लिए यह गर्व और हर्ष का विषय है कि इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे बीकानेर जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समयसीमा में सभी तैयारियां पूर्ण करें, ताकि समारोह का आयोजन गरिमापूर्ण, भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके।

बैठक में बीकानेर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य समारोह के साथ-साथ बीकानेर एवं जयपुर में आयोजित होने वाले 'एट होम' कार्यक्रमों की तैयारियों एवं आयोजन स्थलों से संबंधित व्यवस्थाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर बीकानेर में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रभावी प्रतिबिंब बने तथा उसे आकर्षक एवं यादगार स्वरूप दिया जाए।

बैठक के दौरान बीकानेर जिला कलेक्टर से समारोह स्थल के चयन, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, विद्युत व्यवस्था, परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तथा अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने समारोह में विद्यार्थियों, लोक कलाकारों तथा आमजन की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

# राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध ग्राउंडिंग सुनिश्चित करें : मुख्य सचिव

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए निवेश समझौतों (एमओयू) की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करते हुए नवंबर 2026 तक निर्धारित ग्राउंडिंग लक्ष्य हर हाल में प्राप्त किए जाएं तथा निवेश प्रस्तावों की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अब प्राथमिकता केवल एमओयू पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर उनकी प्रभावी क्रियान्विति एवं डिलीवरी सुनिश्चित करने की है। मुख्य सचिव मंगलवार को शासन सचिवालय में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयू की विभागवार प्रगति एवं नवंबर 2026 तक निर्धारित ग्राउंडिंग लक्ष्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने सभी विभागों को नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रस्ताव एवं फाइलें शीघ्र प्रस्तुत की जाएं तथा संबंधित जिला कलक्टरों के साथ सतत समन्वय स्थापित कर निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा भागीदार है, इसलिए ऊर्जा विभाग सहित सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तेजी से कार्य करें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग शिखर अग्रवाल ने विभागवार प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 11 हजार से अधिक सक्रिय एमओयू के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव विभिन्न चरणों में हैं।

# बाघों की दहाड़ से गूंज रहा राजस्थान: संख्या 149 हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कभी महज 18-20 बाघों तक सिमट चुके राजस्थान के जंगल आज फिर उसकी दहाड़ से गूंज रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस (29 जुलाई) के अवसर पर प्रदेश के पांचों बाघ अभयारण्यों में बाघों की संख्या बढ़कर 149 पहुंच जाना वन्यजीव संरक्षण की बड़ी सफलता का प्रतीक है। हालांकि, बाघों की बढ़ती आबादी के साथ उनके लिए पर्याप्त आवास, नए क्षेत्रों का विकास और गांवों के विस्थापन जैसी चुनौतियां भी तेजी से सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि संरक्षण की इस सफलता को बनाए रखने के लिए अब बाघों के विस्तार के अनुरूप बेहतर प्रबंधन की जरूरत है।

प्रदेश में बाघों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण राजस्थान को अब 'बाघस्थान' कहा जाने लगा है। रणथम्भौर, सरिस्का, धौलपुर-करौली, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य में बाघ, बाघिन और शावकों की संख्या इस वर्ष बढ़कर 149 हो गई है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 135 थी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के.सी. अरुण प्रसाद ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस वर्ष प्रदेश के पांचों बाघ अभयारण्यों में 54 बाघिनों ने 53 शावकों को जन्म दिया है, जबकि वर्ष 2025 में 52 बाघिनों ने 43 शावकों को जन्म दिया था। इस बार सबसे अधिक 28 शावकों का जन्म सरिस्का बाघ अभयारण्य में हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक 72 बाघ (बाघ, बाघिन और शावक) रणथम्भौर बाघ अभयारण्य में हैं, जबकि पिछले वर्ष यहां इनकी संख्या 66 थी। वहीं, सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जो पिछले वर्ष 50 थी। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि बाघों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि प्रदेश के जंगल सुरक्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाघ किसी भी वन पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारी होते हैं और उनकी मौजूदगी पूरे जंगल के स्वस्थ होने का प्रमाण मानी जाती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, करीब दो दशक पहले राजस्थान में बाघों का अस्तित्व संकट में था और प्रदेश में केवल 18 से 20 बाघ ही बचे थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और राजस्थान देश के प्रमुख बाघ आवासों में शामिल हो गया है। वर्तमान में पांचों बाघ अभयारण्यों में वयस्क बाघ-बाघिनों की संख्या करीब 96 है, जबकि शावकों को मिलाकर कुल संख्या 149 तक पहुंच गई है। अकेले रणथम्भौर में लगभग 50 वयस्क बाघ-बाघिन और 22 शावक हैं।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघों के जन्म और उनके जीवित रहने की दृष्टि से रणथम्भौर देश के सबसे सफल बाघ अभयारण्यों में शामिल है। पर्यटन और बाघ देखने के लिए लोगों के आने के लिहाज से भी रणथम्भौर अन्य अभयारण्यों से आगे है।

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, रणथम्भौर का जंगल शुष्क वन क्षेत्र है। घने जंगलों की तुलना में यहां बाघों को देखना अपेक्षाकृत आसान होता है, इसलिए यह देशी-विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि करीब 1,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले रणथम्भौर बाघ अभयारण्य में फिलहाल लगभग 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही बाघों का सक्रिय विचरण है।रणथम्भौर के उपवन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि यहां की सबसे बड़ी ताकत समृद्ध शिकार प्रजातियां हैं। सांभर, चीतल और अन्य शाकाहारी वन्यजीवों की पर्याप्त उपलब्धता तथा विकसित घासभूमि बाघों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है।

विशेषज्ञों ने कहा कि रणथम्भौर में बाघों के जीवित रहने की दर लगभग 80 प्रतिशत है, जो देश के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में सबसे बेहतर मानी जाती है। उन्होंने कहा कि रणथम्भौर का इतिहास बाघिन 'मछली' (टी-16) के बिना अधूरा माना जाता है। करीब दो दशक तक रणथम्भौर पर राज करने वाली इस प्रसिद्ध बाघिन ने 18 शावकों को जन्म दिया। उसके वंशजों ने सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी जैसे अन्य बाघ अभयारण्यों को आबाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 2008 में जब सरिस्का बाघविहीन हो गया था, तब रणथम्भौर की बाघिन 'मछली' के वंशजों के पुनर्वास से वहां फिर बाघों की वापसी हुई। उसकी स्मृति में भारत सरकार ने 2013 में डाक टिकट जारी किया। रणथम्भौर के जोगी महल में उसका स्मारक भी बनाया गया है तथा वन विभाग ने उसके नाम पर 'मछली पुरस्कार' की शुरुआत की है। बाघों की संख्या में वृद्धि वन विभाग के लिए नयी चुनौती भी लेकर आई है। रणथम्भौर में उपलब्ध आवास अब सीमित पड़ने लगा है।

# 100 करोड़ रुपये से अधिक की सभी परियोजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी हों : सम्राट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**पटना/भाषा।** बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राज्य में जारी 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने तथा प्रगति में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार ने विकास की गति पकड़ ली है और अब इसे और तेज करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, चौधरी ने कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के निर्माण कार्य में मानसून के बाद तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और नियमित समीक्षा के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने को कहा।

चौधरी ने नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना' के कार्यों में तेजी लाने और इसे जल्द पूरा कर सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने मंडई वीयर परियोजना की नियमित निगरानी करते हुए इसे समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि राज्य की सिंचाई और जल प्रबंधन व्यवस्था मजबूत हो सके। चौधरी ने वाराणसी-रांची-कोलकाता छह लेन कॉरिडोर, आमस-दरभंगा फोर लेन परियोजना और कन्हौली-शेरपुर (एनएच-131जी) छह लेन परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की स्वीकृति और अन्य प्रशासनिक बाधाओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से सड़क संपर्क बेहतर होगा, आवागमन सुगम बनेगा और राज्य में आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने 'टीबी मुक्त बिहार' अभियान की भी समीक्षा की और अधिक से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग एवं जांच कर संभावित टीबी मरीजों की जल्द पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चौधरी ने अधिक प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने, सभी टीबी केंद्रों को सक्रिय करने और बंद केंद्रों को पुन: शुरू करने को कहा। मुख्यमंत्री ने दो जुलाई से 14 अगस्त, 2026 तक जारी विशेष अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाने, गांवों एवं पंचायतों तक जागरूकता अभियान पहुंचाने, मरीजों को समय पर उपचार, पोषण सहायता और दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में सीएसआर के माध्यम से राज्य में 2,000 करोड़ रुपये का कोष जुटाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा। चौधरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, खेल और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में सीएसआर फंड के प्रभावी उपयोग के लिए उद्योगों एवं कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया।

## सीजेआई ने उच्चतम न्यायालय की इमारत पर अशोक चक्र लगाने से संबंधित याचिका खारिज की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** उच्चतम न्यायालय ने अपनी इमारत पर अशोक चक्र स्थापित किये जाने संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि अदालत इस मामले में खुद फैसला लेगी। 'बाबा खतरनाक' के नाम से भी जाने जाने वाले याचिकाकर्ता बदरावाड़ा वेणुगोपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, 'उच्चतम न्यायालय के गेट पर क्या लगाना है, हम देख लेंगे... दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, उनपर ध्यान दीजिए।'

यह याचिका न्यायालय के मुख्य गुंबद पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र लगाए जाने से जुड़ी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि अदालतों की अपनी एक संवैधानिक पहचान होती है और राष्ट्रीय चिह्न उसका एक हिस्सा होना चाहिए। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, वेणुगोपाल ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मुद्दे पर निर्देश देने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की थी। न्यायालय ने 23 मार्च को इस याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि इस मामले पर मूल रूप से प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अपने महासचिव को निर्देश दिया था कि वह सक्षम प्राधिकारी के सामने इस मामले को रखें।

## प्रधान का किसी 'सुपरस्टार' की तरह स्वागत किया जाना शर्मनाक है : प्रियंका

**नई दिल्ली/भाषा।** कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने संसद परिसर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ सांसदों द्वारा पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किए जाने को लेकर मंगलवार को सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा और कहा कि प्रधान का किसी ''सुपरस्टार'' की तरह स्वागत किया जाना शर्मनाक है। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप भी लगाया कि सरकार छात्रों का दमन करना चाहती है।

उन्होंने कहा, ''सभी ने देखा कि किन परिस्थितियों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन अगले ही दिन संसद परिसर में उनका ऐसा स्वागत किया गया, मानो वह कोई सुपरस्टार हों।'' लोकसभा सदस्य ने कहा, क्या यह शर्मनाक नहीं है? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि आज भी छात्रों को परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले का समाधान बातचीत के माध्यम से करना चाहिए, लेकिन वह अब भी छात्रों के पीछे पड़ी हुई है और उनका दमन करना चाहती है। प्रियंका गांधी का कहना था कि सरकार को छात्रों के प्रति अपना रवैया बदलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद सोमवार को जब पहली बार संसद पहुंचे तो भाजपा के कुछ सांसदों ने उनका स्वागत किया। बिहार के दरभंगा से लोकसभा सदस्य गोपालजी ठाकुर ने उन्हें 'पाग' (मिथिला की पारंपरिक टोपी) पहनाई।

## भाजपा ने प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया : अखिलेश

**नई दिल्ली/भाषा।** समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तंज कसते हुए कहा कि उसने प्रधान का त्यागपत्र लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बचा लिया। सदन में सपा के नेता ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए, वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। यादव ने जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया और कहा कि ''सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''पूर्व शिक्षा मंत्री (प्रधान) जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी...एक प्रधान जी को हटाकर आपने (भाजपा) प्रधानमंत्री बचा लिया।'' सपा नेता ने कहा, ''नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकाने के लिए विवश कर दिया।'' उन्होंने कहा जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है, तब मांगों को स्वीकार कर लेती है।

## लोकसभा में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी गई

**नई दिल्ली/भाषा।** लोकसभा में मंगलवार को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी गई। सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के नामों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ियों शर्मिला धनकड़ ने स्वर्ण पदक और शिल्पा के. शायला ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने सर्वेश कुशारे, वलूरी अजय बाबू तथा ग्यानेश्वरी यादव (रजत पदक) एवं बिंदियारानी देवी (कांस्य पदक) का भी उल्लेख किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कनाडा में आयोजित स्क्वैश चैंपियनशिप, 2026 का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की 18 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इस प्रतिस्पर्धा में खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा, ''मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं।'' बिरला ने कहा, ''जब खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ी पदक जीतते हैं और संसद उनका अभिवादन करती है तो अच्छा संदेश जाता है और खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है।''

## प्रधानमंत्री ने बलात्कारियों का ''बचाव करने वाले'' को शिक्षा मंत्री बनाया : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर युवाओं के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जो बलात्कारियों का बचाव करने वाला है। उन्होंने लोकसभा में पार्टी सदस्य प्रियंका गांधी द्वारा की गई टिप्पणी के बाद शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर निशाना साधा।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिलकीस बानो मामले में दोषियों को जमानत मिलने से संबंधित एक अखबार में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए लोकसभा में जोशी को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिसे कार्यवाही से हटा दिया गया।

इसके बाद संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर युवाओं के प्रदर्शन के बाद भाजपा ने भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है, जो बलात्कारियों का बचाव करता है। इससे अधिक शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति बलात्कारियों को संरक्षण दिए जाने की वकालत करे और वही आज देश का शिक्षा मंत्री हो।''

उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री का कदम अजीब है। उनके मंत्रिमंडल में इतने लोग हैं, वह किसी को भी शिक्षा मंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो बलात्कारियों का बचाव करता है।

प्रियंका गांधी ने जब लोकसभा में इस विषय का उल्लेख किया कि तो सत्तापक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई और इसे शिक्षा मंत्री के खिलाफ निराधार तथा आपत्तिजनक टिप्पणी बताया। सदन में इस मुद्दे पर कुछ देर तक हंगामे की स्थिति भी बनी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नये शिक्षा मंत्री के संबंध में की गई टिप्पणी चरित्र हनन है और बिना सत्यापन के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि प्रियंका गांधी अपने आरोपों को सत्यापित नहीं कर सकतीं तो उन्हें सदन से क्षमा मांगनी चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह की बातें सदन में नहीं कही जानी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाद्रा इस तरह कोई भी आरोप लगाकर बच नहीं सकतीं। उन्होंने मांग की कांग्रेस सांसद सदन से माफी मांगें और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि वह उचित माध्यम से सदन में अपनी बात सत्यापित करेंगी।

## कोलकाता की अदालत ने नीट प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में 16 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**कोलकाता/भाषा।** कोलकाता की एक अदालत ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 16 लोगों को मंगलवार को 30 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सियालदह स्टेशन से मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड तक निकाले गए मार्च के दौरान कुछ लोगों ने पत्रकारों पर हमला किया था, जिससे कई पत्रकार घायल हो गए थे।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन 16 आरोपियों पर हाल ही में लागू किए गए सख्त गुंडा अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद कहा था कि मार्च में हिंसा करने वाले लोगों का नीट प्रश्नपत्र लीक विरोध प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं था और उनपर राष्ट्र विरोधी तत्व होने का संदेह है। राज्य सरकार ने दावा किया कि हिंसा के मामले में जिन कम से कम 70 लोगों की पहचान की गई है, वे न तो छात्र हैं और न ही कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के सदस्य।

सरकार के अनुसार उनका नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ हुए आंदोलन से भी कोई सीधा संबंध नहीं था। राज्य सरकार की ओर से अदालत में पेश वकील ने आरोपियों को हिरासत में रखने की मांग करते हुए कहा कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, तो जांच पर गंभीर असर पड़ेगा।

## जौहर विश्वविद्यालय मामले में मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत तीन अगस्त को करेगी सुनवाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**मुरादाबाद/भाषा।** उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर की 38 संरचनाओं के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले में मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत तीन अगस्त को सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई मंगलवार को प्रस्तावित थी लेकिन सोमवार को एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर आयोजित शोक सभा के बाद वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण इसे टाल दिया गया। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दाखिल अर्जी पर मामले की सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी थी। सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा कि एहतियाती उपाय के तौर पर अंतरिम आदेश जारी किया गया है।

उन्होंने कहा, अगर मंगलवार को न्यायिक कार्य निलंबित रहता और रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) तथा जिला प्रशासन 38 संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ाते तो इससे जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थीं। मंडलायुक्त ने बताया कि अब मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी। इससे पहले 15 जुलाई को आरडीए ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 दिनों के भीतर 40 इमारतों में से 38 को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण का आरोप था कि इन संरचनाओं का निर्माण आवश्यक मंजूरी के बिना किया गया है। ध्वस्तीकरण के लिए दी गई समय-सीमा 30 जुलाई को समाप्त हो रही है। प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

समाजवादी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी कार्रवाई का विरोध करते हुए आदेश वापस लेने की मांग की थी। मंडलायुक्त द्वारा ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद मंगलवार को विद्यार्थियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।

## पूर्व मंत्री की भवन से गिरकर मौत

**लखनऊ/भाषा।** उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नानक राम भुर्जी (68) की मंगलवार को हजरतगंज क्षेत्र स्थित दारुलशफा नए विधायक निवास परिसर के ऊपरी तल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, विधायक निवास के कार्यालय प्रभारी ने स्थानीय चौकी को सूचना दी कि परिसर के पीछे एक ऊपरी तल से एक व्यक्ति गिर गया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और भुर्जी को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरकारी अस्पताल के निदेशक डॉ. जीसी गुप्ता ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि पूर्व मंत्री को अपराह्न करीब ढाई बजे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। उन्होंने बताया कि भुर्जी के शरीर पर चोट के निशान थे और मौत का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा।

## टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को मिला 158.66 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 158.66 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिला, जबकि एक साल पहले यह 155.81 करोड़ रुपये था। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। चंद्रशेखरन को मिला यह अब तक का सर्वाधिक पारिश्रमिक है। टाटा संस ने 2022 से कार्यकारी पारिश्रमिक का खुलासा करना शुरू किया है। पिछले पांच वर्षों में उन्होंने कुल 671.4 करोड़ रुपये कमाए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के उनके पारिश्रमिक में 17.97 करोड़ रुपये वेतन एवं अन्य लाभ के हैं, जबकि 140.69 करोड़ रुपये मुनाफे से जुड़ा कमीशन रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के बराबर है।

इस पारिश्रमिक के साथ चंद्रशेखरन भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले कॉरपोरेट दिग्गजों में शामिल हो गए हैं। एचसीएल टेक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सी. विजयकुमार को वित्त वर्ष 2025-26 में 176 करोड़ रुपये मिले, जबकि पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के सीईओ संदीप कालरा ने 2024-25 में 148 करोड़ रुपये कमाए थे। हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी चेयरमैन पवन मुंजाल को 2025-26 में 122 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिला।

टाटा संस के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) और कार्यकारी निदेशक सौरभ अग्रवाल वित्त वर्ष 2025-26 में 33.69 करोड़ रुपये के पारिश्रमिक के साथ कंपनी में दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी रहे। इसमें 26 करोड़ रुपये का कमीशन भी शामिल है। वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड के बाकी सात सदस्यों को बैठक में शामिल होने के शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं मिला। वहीं निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने टाटा संस के बोर्ड में शामिल होने के बाद से चली आ रही परंपरा के तहत इस बार भी कोई कमीशन नहीं लिया। टाटा समूह की विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी टाटा संस के निदेशक मंडल ने 1,10,717 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है, जिस पर शेयरधारकों की मंजूरी बाकी है।

## मोदी सरकार में नीलेकणी के नेतृत्व वाले कार्यबल की रिपोर्ट भी धूल फांकेगी : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को दावा किया कि मोदी सरकार का अब तक का रिकॉर्ड देखते हुए यह स्पष्ट है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़ी राधाकृष्णन समिति की तरह नए कार्य बल की रिपोर्ट भी धूल फांकेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में लगातार गड़बड़ियों के बाद मोदी सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देने के लिए के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। उन्होंने कहा कि समिति ने कुल 101 सिफारिशें की थीं, जिनमें 60 अल्पकालिक, 30 मध्यम अवधि की और छह सरकार के लिए थीं।

कांग्रेस महासचिव ने अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित विश्लेषण का हवाला देते हुए दावा किया कि समिति की 101 सिफारिशों में से 27 अब तक लागू नहीं की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मामले में देश को जानबूझकर गुमराह किया। रमेश के मुताबिक, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिसंबर, 2024 में घोषणा की थी कि समिति की सिफारिशों के अनुरूप एनटीए अब भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद एनटीए ने 2025 और 2026 में कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित कीं। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि 2024 और 2026 के कथित पेपर लीक मामलों के बीच करीब दो वर्षों तक एनटीए में पूर्णकालिक महानिदेशक की नियुक्ति नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने की न तो सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति थी और न ही ईमानदार मंशा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब नंदन नीलेकणी की अगुवाई में उच्चस्तरीय कार्यबल किस मुंह से बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया, सरकार के अब तक के रिकॉर्ड को देखते हुए इस कार्यबाल की रिपोर्ट भी धूल फांकेगी।''

## सुविचार

**आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। अपने आप पर भरोसा रखें, डर को पीछे छोड़ें, हिम्मत से आगे बढ़ें, मंजिल निकट आएगी।**

## दक्षिण भारत राष्ट्रमत

# वांगचुक भूखे रहे, 'क्रांतिवीरों' ने पकवान उड़ाए

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जब से अपना अनशन खत्म किया है, उन पर उलाहनों की बौछार हो रही है। वे कल तक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की आंखों के तारे थे। अब इल्ज़ामों के तीखे तीर झेल रहे हैं। लद्दाख का एक व्यक्ति दिल्ली की गर्मी में 26 दिनों तक भूखा बैठा रहा, लेकिन सीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि 'वांगचुक को अपना अनशन लंबा खींचना चाहिए था, ताकि केंद्र सरकार पर और दबाव पड़ता, कुछ और मंत्रियों के इस्तीफे होते।' यह सुझाव देने वाले खुद तो जंतर-मंतर पर पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, समोसे, नूडल्स, मोमोज, सैंडविच, डोसा, छोले-भटूरे और कई पकवानों पर हाथ साफ कर रहे थे, लेकिन वांगचुक को भूखा रखना चाहते थे, ताकि देश में राजनीतिक अस्थिरता फैले। यह कैसी सोच है, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी के जीवन की परवाह नहीं करती है? आज देश में बहुत लोग यह कहते हुए दिल्ली पुलिस की निंदा कर रहे हैं कि वह वांगचुक को उठाकर अस्पताल ले गई थी, इसलिए प्रदर्शनकारी भड़के और वे संसद भवन की ओर चल पड़े थे। सोचिए, अगर दिल्ली पुलिस उन्हें अस्पताल न ले जाती तो क्या होता? वांगचुक खुद एक वीडियो में स्वीकार कर चुके हैं कि अनशन की वजह से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। अगर सोनम वांगचुक धरना स्थल पर ही रहते तो उनकी तबीयत बिगड़ती और प्राणों पर बहुत बड़ा संकट मंडराता। उस स्थिति में सीजेपी के कथित क्रांतिवीर और उन्हें पर्दे के पीछे से समर्थन दे रहे संगठन हंगामा खड़ा करते कि देश की राजधानी में एक इन्सान ने भूख से तड़पकर दम तोड़ दिया।

उससे कानून व्यवस्था का कितना बड़ा संकट पैदा होता? आज जो 'क्रांतिवीर' कह रहे हैं कि 'वांगचुक को अनशन तोड़ने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मंत्री के हाथ से गिलास लेने की जरूरत नहीं थी, शर्तों में स्पष्टता के लिए कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए था', वे उनके नाम पर अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने के चक्कर में थे। चूंकि ऐसे मामलों में सहानुभूति की लहर चलती है, इसलिए जो व्यक्ति उस नाम का सहारा लेकर चुनावी मैदान में कूदता है, उसे फायदा मिलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। वांगचुक अभी स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें पहले जैसी स्थिति तक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। वहीं, सीजेपी के 'नौनिहाल' क्या कर रहे हैं? एक आलीशान होटल में जश्न मनाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है! दूसरों से आदर्श, नैतिकता, संयम, सदाचार और तपस्या की उम्मीद करने वाले खुद मौज उड़ा रहे हैं! ये न जरा-सी भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, न प्यास झेल सकते हैं, न पार्टी करने का मौका गंवा सकते हैं! हां, इनके लिए कोई और भूखा रह जाए, कोई और प्यासा रह जाए, वह इन्हें खुशी-खुशी कबूल है। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक बहुत दु:खी नजर आए थे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की ओर से उन पर दबाव डाला जा रहा था। क्या अनशन कोई सजावटी सामान है, जिसके लिए फ़रमाइश की जाए कि ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए? वांगचुक भी इसे महसूस कर रहे हैं। अगर न करते तो ऐसा कभी नहीं कहते कि 'अपने भाइयों, बहनों और छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें मेरा 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं ... दिल्ली की तपती धूप में यह सब करने के बाद क्या मुझे किसी से चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा? उसके हाथों क्यों तोड़ा? इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा? क्या सौदा हुआ? यह सब मुझे जवाब देना होगा?' ऐसा प्रतीत होता है कि वांगचुक का भी अन्ना की तरह इस्तेमाल किया गया है।

## ट्वीटर टॉक

एग्जामिनेशन सिस्टम का भरोसेमंद होना और ट्रांसपेरेंसी देश के हित का एक अहम मामला है। इस विषय पर गहरी चर्चा और गंभीर सोच-विचार ज़रूरी है। जब रूलिंग पार्टी और अपोज़िशन दोनों 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, 2026' पर चर्चा के लिए राज़ी हो गए हैं।

**-ओम बिरला**

भारतीय दर्शन और सनातन संस्कृति में, गुरु को साक्षात परम ब्रह्म माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का पवित्र त्योहार हम सभी के लिए अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आभार और सम्मान दिखाने का मौका है। सच तो यह है कि गुरु सिर्फ़ शिक्षा ही नहीं देते; वे जीवन को रास्ता भी दिखाते हैं।

**-योगी आदित्यनाथ**

आज मैंने राज्य के युवा साथियों से दिल से बात की, उनके विचारों, इनोवेशन और एक विकसित राजस्थान के लिए उनके इरादे के बारे में जाना। उनकी एनर्जी, टैलेंट और इनोवेटिव सोच हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है।

**-भजनलाल शर्मा**

## प्रेरक प्रसंग

# गर्भ से ब्रह्मज्ञान तक

आयुर्वेद की कक्षा में एक छात्र ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मनुष्य को न तो अपने जन्म का पता चलता है और न ही अपनी मृत्यु का। फिर जीवन और मृत्यु का वास्तविक रहस्य क्या है? गुरु बोले, जैसे तृण-जलायुका (जोंक) घास के एक तिनके के अंतिम सिरे तक पहुंचकर पहले दूसरे तिनके को दृढ़ता से पकड़ती है और उसके बाद ही पहले तिनके को छोड़ती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने संचित कर्मों और वासनाओं के अनुसार अगले शरीर का आधार प्राप्त करती है। और वह पुराने शरीर से अपना संबंध समाप्त कर देती है। गुरु ने आगे समझाया कि नया शरीर प्राप्त करने की प्रक्रिया माता के गर्भ के माध्यम से होती है। गर्भ ही वह सेतु है जिसके द्वारा जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा पूर्ण करती है। गर्भ तम से ढक जाता है जिसके कारण उसके पहले जन्म की बातों का स्मृति नाश हो जाता है। इसलिए उसे पूर्वजन्म की बातें याद नहीं रहती। अगला शरीर उसको संचित कर्मों और वासनाओं के अनुसार अगला जन्म मिलता है। इसी कारण जीव बार-बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र में जोंक की भांति एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहता है।

## सामयिक

**उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सत्ता का मार्ग तय करती आई है। ओवैसी द्वारा अखिलेश यादव की तरफ बढ़ाया गया हाथ और उस पर कांग्रेस की चिंताएं यह दर्शाती हैं कि राज्य में चुनावी जंग अब केवल विकास या जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं रह गई है। यह विचारधाराओं, पहचान की राजनीति और रणनीतिक वर्चस्व की एक बेहद पेचीदा लड़ाई बन चुकी है।**

# उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरणों की आहट और कांग्रेस!

**अशोक भाटिया**
**मोबाइल : 9221232130**

उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक बार फिर करवट लेनी शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे बड़ी चर्चा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच संभावित नजदीकियों को लेकर है। हैदराबाद से चलकर हिंदी पट्टी, विशेषकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे ओवैसी ने जिस तरह से अखिलेश यादव को गठबंधन का खुला प्रस्ताव दिया है, उसने राज्य के पुराने चुनावी गणित को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। मुरादाबाद की रैली में ओवैसी का यह कहना कि भाजपा को रोकने के लिए हम समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हैं, बशर्ते हमें हमारा वाजिब हक मिले, केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के भीतर सुलग रही राजनीतिक आकांक्षाओं और असुरक्षा की भावना को एक नया मंच देने का प्रयास है।

इस पूरे घटनाक्रम ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण की राजनीति को नए सिरे से धार देने का मौका दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ 'इंडि' गठबंधन के भीतर एक बड़ा रणनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। इस संकट के केंद्र में सबसे अधिक कोई पार्टी प्रभावित दिख रही है, तो वह कांग्रेस है। पिछले कुछ चुनावों से उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस के लिए सपा और ओवैसी के बीच बढ़ती यह नजदीकी एक गहरी असमंजस की स्थिति लेकर आई है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी का हाथ थामेंगे? और यदि ऐसा होता है, या केवल इसकी सुगबुगाहट भी बनी रहती है, तो कांग्रेस इस नए चक्रव्यूह से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी? असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि वे बिना सोचे-समझे कोई बिसात नहीं बिछाते। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19 से 20 प्रतिशत है, जो दर्जनों लोकसभा और विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। पारंपरिक रूप से यह मतदाता वर्ग समाजवादी पार्टी और कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की तरफ झुकता रहा है। ओवैसी ने मुरादाबाद की धरती से जो संदेश दिया, वह बहुत साफ था-मुस्लिम समुदाय अब केवल दरी बिछाने और दूसरों को सत्ता तक पहुंचाने का जरिया नहीं बनेगा, उसे सत्ता में आनुपातिक हिस्सेदारी चाहिए।

ओवैसी का यह रुख अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी राजनीतिक दुविधा पैदा करता है। यदि अखिलेश ओवैसी को पूरी तरह खारिज करते हैं, तो ओवैसी उन पर 'मुस्लिम विरोधी' या 'मुसलमानों के वोटों का फायदा उठाने वाले नेता' का ठप्पा लगाकर अल्पसंख्यक मतों में सेंधमारी कर सकते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने भले ही खुद ज्यादा सीटें न जीती हों, लेकिन उसने धर्मनिरपेक्ष दलों का खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। यदि अखिलेश यादव ओवैसी से हाथ मिला लेते हैं, तो भाजपा को मुस्लिम तुष्टीकरण और कट्टरपंथ के तुष्टीकरण का नैरेटिव बनाने का सीधा मौका मिल जाएगा। इससे सपा की 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति का गैर-मुस्लिम हिस्सा, विशेषकर पिछड़ी और अगड़ी जातियों का वह वर्ग जो भाजपा से नाराज होकर सपा की तरफ आ सकता है, तुरंत छिटककर वापस भाजपा के पाले में चला जाएगा।अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ओवैसी के साथ मंच साझा करने की एक भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसे उनका पारंपरिक गैर-मुस्लिम वोट बैंक शायद स्वीकार न करे। इस पूरी सियासी बिसात में कांग्रेस पार्टी सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कांग्रेस के सामने यह संकट केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति और 'इंडि' गठबंधन की एकजुटता पर भी पड़ना तय है। कांग्रेस के रणनीतिकारों के सामने इस समय तीन बड़ी चुनौतियां हैं। पहली कांग्रेस खुद को देश की सबसे बड़ी और स्वाभाविक धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है। उत्तर प्रदेश में वह सपा के साथ गठबंधन में रहकर खुद को अल्पसंख्यकों के रक्षक के रूप में पेश करती रही है। लेकिन अगर ओवैसी इस त्रिकोण में प्रवेश करते हैं, तो वे कांग्रेस के इस नैरेटिव को सीधे चुनौती देंगे।दूसरी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की छोटे भाई वाली भूमिका से बाहर निकलकर अपनी सीटों की संख्या और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहती है। यदि सपा और ओवैसी के बीच कोई परोक्ष या अपरोक्ष समझौता होता है, तो गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे का गणित पूरी तरह बिगड़ जाएगा।

तीसरी कांग्रेस की राष्ट्रीय रणनीति इस समय सॉफ्ट-हिंदुत्व, जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के इर्द-गिर्द घूम रही है। वह बहुसंख्यक समाज के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ओवैसी और सपा की दोस्ती की खबरें सुर्खियों में रहती हैं, तो भाजपा पूरे चुनाव को 'राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण' के ध्रुवों पर केंद्रित कर देगी।

ऐसी हालात में कांग्रेस समाजवादी पार्टी नेतृत्व को यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश करेगी कि 'इंडि' गठबंधन की एकजुटता के लिए ओवैसी जैसे तत्वों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। कांग्रेस का तर्क होगा कि ओवैसी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन पूरे देश में गठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।

वह अखिलेश यादव को यह याद दिलाएगी कि अगर वे उत्तर प्रदेश के बाहर (जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार में) एक गंभीर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और सर्वसमावेशी ढांचे के साथ चलना होगा, न कि किसी क्षेत्रीय या समुदाय-विशेष की राजनीति करने वाले दल के साथ। केवल ओवैसी की आलोचना करने से कांग्रेस का काम नहीं चलेगा। उसे मुस्लिम समाज के भीतर ओवैसी के प्रति बढ़ते आकर्षण को रोकना होगा। इसके लिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग, धर्मगुरुओं और युवाओं के बीच सीधे जाकर यह संदेश देने की योजना बना रही है कि देश के स्तर पर भाजपा का मुकाबला केवल कांग्रेस ही कर सकती है, कोई क्षेत्रीय दल नहीं। कांग्रेस अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखेगी और यह साबित करने की कोशिश करेगी कि भावुक बयानों के बजाय व्यावहारिक राजनीति ही उनका भला कर सकती है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पर्दे के पीछे भाजपा इस पूरी हलचल पर पैनी नजर रखे हुए है। भाजपा के लिए ओवैसी और अखिलेश की दोस्ती की 'आहट' भी एक बड़े सियासी वरदान जैसी है। भाजपा इस स्थिति का उपयोग अपने मुख्य एजेंडे को धार देने के लिए करेगी।तब भाजपा जनता के बीच यह संदेश ले जाने में तनिक भी देर नहीं करेगी कि सत्ता पाने के लिए सपा और कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि ओवैसी जैसी राजनीति का समर्थन भी कर सकते और यदि ओवैसी अलग चुनाव लड़ते हैं, तो वे विपक्ष के वोट काटेंगे; यदि वे सपा के साथ आते हैं, तो बहुसंख्यक वोट एकजुट होकर भाजपा की तरफ आएंगे। दोनों ही सूरतों में भाजपा के लिए यह 'विन-विन' यानी हर हाल में फायदे वाली स्थिति बनती दिख रही है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सत्ता का मार्ग तय करती आई है। ओवैसी द्वारा अखिलेश यादव की तरफ बढ़ाया गया हाथ और उस पर कांग्रेस की चिंताएं यह दर्शाती हैं कि राज्य में चुनावी जंग अब केवल विकास या जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं रह गई है। यह विचारधाराओं, पहचान की राजनीति और रणनीतिक वर्चस्व की एक बेहद पेचीदा लड़ाई बन चुकी है। कांग्रेस के लिए यह समय आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर ठोस फैसले लेने का है। उसे यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मतदाता अब केवल 'भाजपा के डर' से किसी को वोट देने के मूड में नहीं है, वह अपनी राजनीतिक पहचान और सम्मान चाहता है। ओवैसी इसी नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कांग्रेस ओवैसी के इस उभार को रोकने में नाकाम रहती है, या अखिलेश यादव को एक आत्मघाती कदम उठाने से नहीं रोक पाती, तो उत्तर प्रदेश में 'इंडिया' गठबंधन का भविष्य संकट में पड़ सकता है। आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि कांग्रेस इस राजनीतिक बिसात पर शह और मात के खेल में खुद को किंगमेकर के रूप में स्थापित रख पाती है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के हाशिये पर धकेल दी जाती है।

## नजरिया

# गुरु महिमा अपरंपार

**बाल मुकुन्द ओझा**
**मोबाइल : 9414441218**

गुरु के प्रति आदर सम्मान को व्यक्त करने के लिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस बार यह बुधवार, 29 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। जीवन में गुरु और शिक्षक के महत्व को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए यह पर्व आदर्श है। सनातन परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। हमारी वैदिक संस्कृति में गुरु की महिमा का बखान प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों आदि सब में मिलता है। हमारा देश गुरु शिष्य परंपरा का अनुपम उदहारण है. इस देश में युगों युगों से गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। गुरु ही वह इंसान है जो सही राह दिखता है। देश के महान संत कबीर ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। संत कबीर ने गुरु को को गोविंद से भी ऊँचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं।

भारत की संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उनके बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव मानी गई है। भारतीय संस्कृति में गुरु का विशेष महत्व है। मान्यता है कि प्राचीन काल में इसी दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते थे। गुरु और शिक्षक में भी अंतर बताया गया है। शिक्षक अक्षर ज्ञान कराता है वहीं गुरु जीवन का ज्ञान । प्राचीन समय से ही गुरु ज्ञान के प्रसार के साथ-साथ समाज के विकास का बीड़ा उठाते रहे हैं। जीवन में अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने वाला गुरु होता है। गुरु अज्ञान को दूर कर हमें ज्ञान का प्रकाश देता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में गुरु के महत्त्व पर बल देता है। गुरु बच्चों को ज्ञानवान और सुसंस्कृत बनाते हैं। बच्चा घर से निकल कर विद्यालय में प्रवेश लेता है तो गुरु ही उसका अभिभावक होता है। बच्चों में अच्छे संस्कार गुरु ही डालता है। संस्कारवान बच्चे में देश सेवा का जज्बा होता है। विद्यालय से निकलकर वे देश सेवा का का व्रत लेते है।

भारत में गुरूकुल की शिक्षा को आज भी याद किया जाता है। गुरूकुल की शिक्षा में हमारे आपसी सम्बन्धों, सामाजिक सांस्कृतिक एकता, गौरवशाली परम्पराओं को प्रमुखता से केन्द्र बिन्दु में रखा जाता था ताकि बालक पढ़ लिखकर चरित्रवान बने और उसमें नैतिक संस्कारों का समावेश हो। द्रोणाचार्य का उदाहरण हमारे सामने है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बताया था और गुरु ने शिष्य से उसका अंगूठा ही मांग लिया। गुरु शिष्य परम्परा में दुनियां में ऐसे उदाहरण मिलना मुश्किल है।

यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे । उन्होंने चारों वेदों की भी रचना की थी। इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदिगुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। मां-बाप के बाद अगर जीवन में किसी का विशेष स्थान होता है तो वह हैं हमारे गुरु। जिस बच्चे को माता-पिता जन्म देता है, उसे जीवन की कठिन और काँटों भरी राह पर मजबूती से खड़े रहने की हिम्मत एक गुरु ही देता है।

आज गुरु शिष्य परम्परा लगभग समाप्त होती जारही है। एक दूसरे के प्रति अनुराग श्रद्धा और प्रेम की भावना नहीं रही है। गुरु शब्द ही खत्म हो गया है। गुरु का स्थान शिक्षक ने ले लिया है। सरकारी सेवा में आने के बाद शिक्षक केवल अपने काम से मतलब रखता है। शिष्य पढ़ रहा है या नहीं इससे कोई सरोकार नहीं है। शिक्षक का ध्यान अपने वेतन भत्तों पर ज्यादा रहता है। हड़ताल जैसे उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। सही तो यह है आज जो शिक्षा बच्चों को दी जारही है उसमें संस्कार का नितांत अभाव है। बच्चा पढ़े तो ठीक है और न पढ़े तो भी ठीक है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि विद्यालय में न तो बच्चा पढ़ना चाहता है और न अध्यापकों की शिक्षण में कोई रुचि है। गुरूकुल की शिक्षा पद्धति के स्थान पर मैकाले की शिक्षा प्रणाली अपनाकर हमने यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का अंधानुकरण किया जिसके वैश्विक परिणाम हमारे सामने है। हम अपने माता-पिता के सम्बन्धों को भूल गये हैं, चरित्र और नैतिकता का स्थान सिर्फ डिग्री और प्रमाण पत्र बटोरना रह गया है ताकि मैकाले की शिक्षा पर चलकर हम नौकर बन सके। शारीरिक सुखसाधनों को अपना सकें। संस्कारों और गौरवशाली सम्बन्धों का त्याग कर खुद की प्रगति ही अब सब कुछ हो गई है। इसमें अर्थोपार्जन की भूमिका अधिक बढ़ गई है। भौतिक साधनों की प्राप्ति अहम हो गई है। देश सेवा, प्रेम और उच्च नैतिक मानदण्डों का इससे निरन्तर क्षरण हो रहा है। मूल्य आधारित शिक्षा का स्थान सुख सुविधा ने ग्रहण कर लिया है। आज जरुरत इस बात की है कि हम अनुशासन और समर्पण की भावना का अंगीकार कर आगे बढे तभी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी।

**आज गुरु शिष्य परम्परा लगभग समाप्त होती जारही है। एक दूसरे के प्रति अनुराग श्रद्धा और प्रेम की भावना नहीं रही है। गुरु शब्द ही खत्म हो गया है। गुरु का स्थान शिक्षक ने ले लिया है। सरकारी सेवा में आने के बाद शिक्षक केवल अपने काम से मतलब रखता है। शिष्य पढ़ रहा है या नहीं इससे कोई सरोकार नहीं है।**

महत्त्वपूर्ण
Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गुरु पूर्णिमा

गुजरात के सूरत स्थित ज्ञानगंगा विद्यालय में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने शिक्षक को फूल भेंट करते छात्र।एष्ठ

# नीट प्रदर्शन मामले में न्यायालय ने बेदाग रिकॉर्ड वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राज्यों को हाल ही में हुए छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया और निर्देश दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को रिहा किया जाए, जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक होने को लेकर देशभर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जरूरत है।

पीठ ने कहा, ''जिस किसी ने भी ज्यादती की है या कानून को अपने हाथ में लिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।'' शीर्ष अदालत ने पैलेट गन, कील लगी लाठियों और इलेक्ट्रिक बैटन' के इस्तेमाल जैसे आरोपों पर संज्ञान लिया, जिनकी वजह से कई छात्रों और युवतियों को गंभीर और जानलेवा चोटें आईं। पीठ ने कहा कि वह एक कार्यबल के जरिए सभी आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और गहन जांच कराने पर विचार कर रही है। पीठ ने कहा कि इस बात का पता लगाने के लिए भी जांच की जरूरत है कि 250 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले छात्रों ने किये थे या 'कुछ उपद्रवियों' ने।

पीठ ने उन राज्यों को कई अंतरिम निर्देश जारी किए, जहां विरोध प्रदर्शन हुए थे, ताकि प्रदर्शनों से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी-कैमरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, पीसीआर प्रविष्टियां और अन्य डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखा जा सके। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया गया कि प्रदर्शनकारियों से जुड़ा जो भी डिजिटल डेटा इकट्ठा किया गया है, उसे सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने के साथ ही स्पष्ट किया कि उसका यह निर्देश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है।

न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मामले में दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर जांच जारी रखने अनुमति दे दी, लेकिन यह भी कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से भी जवाब तलब किया।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, प्रथम दृष्टया इन आरोपों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए, जिसमें घायल हुए 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि किसी स्वतंत्र समिति या विशेष जांच दल (एसआईटी)के गठन पर विचार करने से पहले केंद्र और संबंधित राज्यों को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया जाता है। न्यायालय ने कहा कि ''निर्धारित प्रोटोकॉल'' का उल्लंघन होने पर कानून अपना काम करेगा। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि वह एसआईटी की संरचना के बारे में बाद में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करेगा।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अब समय आ गया है कि अदालतों द्वारा समय-समय पर तय किए गए सभी कानूनी सिद्धांतों को एक साथ लाया जाए और विरोध-प्रदर्शनों की स्थिति को अब एक जैसे मापदंडों के तहत नियंत्रित किया जाए।

## दक्षिण दिल्ली में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत

नई दिल्ली/भाषा। दक्षिण दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में 28 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका एक साथी घायल हो गया। यह जानकारी मंगलवार को एक अधिकारी ने दी। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के संबंध में देर रात 12 बजकर 41 मिनट पर पुल प्रहलादपुर थाने को सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम को मौके पर भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार, मृतक की पहचान मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू (28) के तौर पर हुई है, जिसे कई गोलियां लगीं। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में इरशाद के साथी 27 वर्षीय मोहम्मद फारुक के हाथ में गोली लगी, जिसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और उपचार के बाद उसे छुट्टी दे गई। अपराध टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने अपराध स्थल का निरीक्षण किया तथा सबूत एकत्र किए। पुलिस ने मौके से कारतूस के 10 खोखे और दो कारतूस बरामद किए, जिन्हें जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीम गठित की गई हैं। जांचकर्ता आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं, जबकि आरोपियों का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी और जांच के अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। हत्या के पीछे का मकसद अब तक पता नहीं चल सका है और जांचकर्ता व्यक्तिगत दुश्मनी तथा आपराधिक संबंधों सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

## दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का दिया आदेश : आरबीआई

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को बंद करने का आदेश दिया है। आरबीआई ने अप्रैल, 2026 में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के चलते पीपीबीएल का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने पीपीबीएल का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल पाया था। इसके बाद आरबीआई ने उच्च न्यायालय में बैंक को बंद करने की याचिका दायर की थी।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ''दिल्ली उच्च न्यायालय ने आठ जुलाई और 22 जुलाई के आदेशों के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए पीपीबीएल को बंद करने का निर्देश दिया है।'' इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरिकुमार एम नायर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया। आरबीआई ने न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि परिसमापक आठ जुलाई, 2026 से बैंक के निदेशक मंडल को हासिल सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ऑनलाइन भुगतान मंच पेटीएम की सहयोगी फर्म पीपीबीएल पर पहले भी कई बार नियामकीय कार्रवाई हो चुकी है। इस पर 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। बाद में 2024 में इसकी जमा और अन्य सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे।

## मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने धोनी को बनाया ब्रांड एम्बैसडर

नई दिल्ली/भाषा। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बैसडर बनाया है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, विविध कारोबार वाले भारतीय समूह मलाबार ग्रुप की प्रमुख कंपनी है। इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। कंपनी के 14 देशों में 450 से अधिक शोरूम हैं। मालाबार समूह के चेयरमैन एम.पी. अहमद ने मंगलवार को जारी बयान में कहा, आज उपभोक्ता जिस भी ब्रांड का चयन करता है उससे काफी अपेक्षाएं रखता है। उत्कृष्ट उत्पादों के साथ वे हर खरीदारी में पारदर्शिता, प्रामाणिकता और भरोसा भी चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि धोनी ने अपनी ईमानदारी, अनुशासन और निरंतरता के दम पर करोड़ों लोगों का सम्मान और विश्वास अर्जित किया है। ये खूबियां कंपनी के मूल्यों से भी मेल खाते हैं। इसी वजह से उन्हें ब्रांड एम्बैसडर बनाया गया है। धोनी ने कहा, ''अपने पूरे करियर में मेरा यही मानना रहा है कि काम और निरंतरता के दम पर ही भरोसा अर्जित किया जाता है। यही बात मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ मेरे इस जुड़ाव को सार्थक बनाती है।'' धोनी ने कहा कि वह लोगों को आभूषण खरीदने के बारे में सोच-समझकर फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित करने में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का सहयोग करेंगे।

## गुकेश और सिंदारोव के बीच शतरंज विश्व चैम्पियनशिप मैच नवंबर-दिसंबर में जिनेवा में

जिनेवा/भाषा। मौजूदा चैम्पियन डी गुकेश और चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव के बीच फिडे विश्व चैम्पियनशिप मैच 2026 स्विटजरलैंड के जिनेवा में 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच खेला जायेगा। भारत के गुकेश और उजबेकिस्तान के सिंदारोव मैच के समय सिर्फ 20 वर्ष के होंगे जिससे यह विश्व चैम्पियनशिप के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला मुकाबला होगा। फिडे के अंतरिम अध्यक्ष विश्वनाथन आनंद ने इसका स्वागत करते हुए कहा, ''भारत, अमेरिका और साइप्रस समेत कई देशों ने फिडे विश्व चैम्पियनशिप मैच की मेजबानी की इच्छा जताई थी।''

विश्व चैम्पियनशिप मैच में 14 क्लासिकल मुकाबले होंगे और 7.5 अंक तक पहले पहुंचने वाला खिलाड़ी विश्व चैम्पियन बनेगा। कोई भी खिलाड़ी इतने अंक तक पहुंच जायेगा तो बाकी मुकाबले नहीं होंगे। स्कोर 7.7 से बराबर रहने पर कई टाइब्रेकर खेले जायेंगे। पांच बार के विश्व चैम्पियन आनंद ने कहा, ''सभी प्रस्तावों पर गौर करने के बाद यह तय किया गया कि मुकाबला तटस्थ स्थान पर हो। इसके लिये जिनेवा को चुना गया चूंकि यह शहर देशों और संस्कृतियों को करीब लाता रहा है।'' गुकेश ने 2024 में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब जीता था। वह सबसे युवा विश्व चैम्पियन हैं।

## व्हाइट में श्रीश्री रविशंकर के किरदार में दिखेंगे विक्रांत मैसी

मुंबई/एजेन्सी '12वीं फेल' जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता विक्रांत मैसी अब बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार में नजर आने वाले हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'व्हाइट' में वह वैश्विक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म को लेकर निर्माता महावीर जैन ने बड़ा दावा किया है कि विक्रांत का यह अभिनय दुनियाभर के दर्शकों को प्रभावित करेगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निर्माता महावीर जैन ने फिल्म को लेकर अपनी बात साझा की। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया युद्ध, हिंसा और लगातार बढ़ते संघर्षों से जूझ रही है। ऐसे समय में 'व्हाइट' जैसी फिल्म लोगों के सामने शांति और समाधान का संदेश लेकर आ रही है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक सोच और जीवन मूल्यों को दुनिया तक पहुंचाने का एक माध्यम है। यह भारत की ओर से पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार साबित हो सकती है।

शुभारंभ

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को नई दिल्ली में 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के पोर्टल का शुभारंभ किया, जो पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने की एक कल्याणकारी योजना है। इस अवसर पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे।

## रेखा को मिलेगा आईएफएफएम में खास सम्मान

मुंबई/एजेन्सी

मशहूर अभिनेत्री रेखा को 'भारतीय फिल्म ऑफ मेलबर्न 2026' में भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही, उनकी क्लासिक फिल्म 'उमराव जान' को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यह फिल्म महान गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदर्शित की जाएगी। अभिनेत्री का कहना है कि फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया किरदार उनकी यादों और चुप्पी में जिंदा है। रेखा ने कहा, उमराव जान ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वह मेरी यादों, खामोशियों और उन लोगों के दिलों में जिंदा है, जिन्होंने इतने सालों में उन्हें बहुत प्यार और अपनापन दिया। उस सफर को फिर से देखना और फिल्म को ग्लोबल मंच पर सेलिब्रेट करते देखना, विनम्र और दिल छूने वाला है।अभिनेत्री ने आगे कहा, सिनेमा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और 'आईएफएफएम 2026' में 'एक्सीलेंस इन सिनेमा अवॉर्ड' से सम्मानित होना खास है। मैं इस सम्मान को तहे दिल से स्वीकार करती हूं, ने सिर्फ अपनी यात्रा के पहचान के तौर पर, बल्कि उन फिल्ममेकर्स, लेखकों, म्यूजिशियंस और अनगिनत सहयोगियों को श्रद्धांजलि देने के तौर पर भी, जिन्होंने मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया और मेरे काम को आकार दिया।फेस्टिवल की खास इंडिपेंडेंस डे परंपरा के तहत, रेखा 15 अगस्त को मेलबर्न में इंडियन नेशनल फ्लैग फहराएंगी। यह भारत के 79वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर होगा। उनके साथ इंडियन डायस्पोरा के सदस्य, ऑस्ट्रेलियाई जाने-माने लोग, फिल्ममेकर, कलाकार और सिनेमा लवर भी होंगे।

## शिल्पा शेट्टी ने आरक्षण विवाद पर तोड़ी चुप्पी, वायरल बयान को बताया झूठा और निराधार

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए बताया कि रिजर्वेशन पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह से फर्जी और निराधार है। साथ ही, अभिनेत्री ने ऐसी खबरों पर भरोसा न करने की सलाह दी। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे नाम से जोड़कर आरक्षण को लेकर फैलाए जा रहे झूठे बयानों को देखकर मैं हैरान हूं। यह पूरी तरह से फर्जी, दुर्भावनापूर्ण और झूठी खबर है। इस नकली खबर पर भरोसा न करें। बात दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन की समाप्ति के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन (आरएचए) नामक नया डिजिटल अभियान शुरू किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरएचए पर कई सेलेब्स ने प्रतिक्रिया दी थी।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने एक

नोट जारी करते हुए लिखा था, आरक्षण को मत छेड़िए। सामान्य वर्ग के डॉक्टरों को केवल सामान्य वर्ग के मरीजों का इलाज करने दें और बाकी सभी वर्गों के डॉक्टरों को केवल अपनी-अपनी जाति के मरीजों का इलाज करने दें। ऐसा कुछ सालों तक करके देखिए, फिर लोग खुद जाति आधारित आरक्षण खत्म करने की मांग करने लगेंगे। आरक्षण से कौशल हासिल नहीं किया जा सकता। अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही पोस्ट में अभिनेत्री पर आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने जाति-आधारित रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ कड़े बयान दिए थे। दावे के मुताबिक, एक्टर ने जाति के आधार पर अलग मेडिकल ट्रीटमेंट की वकालत की।

## बहन ने खींची तस्वीरें और खुल गया बॉलीवुड का रास्ता : कृति सेनन

मुंबई/एजेन्सी

आज बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में शामिल कृति सेनन को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। खूबसूरती, अभिनय और अलग-अलग तरह के किरदारों के दम पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन उनके इस सफर की शुरुआत किसी बड़े स्टूडियो से नहीं, बल्कि घर के एक छोटे से फोटोशूट से हुई थी। उनकी बहन नूपुर सेनन ने जब कैमरे से कृति की कुछ तस्वीरें क्लिक कीं, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही तस्वीरें आगे चलकर उनके सपनों की पहली सीढ़ी बन जाएंगी। कृति सेनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता राहुल सेनन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जबकि उनकी मां गीता सेनन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं। उन्होंने दिल्ली से स्कूली शिक्षा हासिल की और इसके बाद नोएडा एक इंस्टीट्यूट से बीटेक किया। कॉलेज के दिनों तक कृति ने कभी नहीं सोचा था कि वह अभिनेत्री बनेंगी। वह पढ़ाई में काफी अच्छी थीं। पढ़ाई के दौरान उनकी लंबी हाइट और आत्मविश्वास देखकर दोस्तों ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। शुरुआत में कृति को यह बात अजीब लगी क्योंकि उन्होंने कभी कैमरे के सामने आने के बारे में नहीं सोचा था। फिर भी उन्होंने एक बार किस्मत आजमाने की सोची। इसमें उनका साथ उनकी बहन नूपुर ने दिया। कृति के पास कोई प्रोफेशनल पोर्टफोलियो नहीं था। उन्होंने अपनी बहन से कुछ तस्वीरें खींचने के लिए कहा।

नूपुर ने घर पर ही कृति की तस्वीरें क्लिक कीं, जिसे कृति ने एक ऑनलाइन मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के लिए भेज दिया। किस्मत ने साथ

दिया और वह कॉन्टेस्ट जीत गईं। इसके बाद उन्हें मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ पोर्टफोलियो शूट करने का मौका मिला। यही मौका उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत बना।

मॉडलिंग के बाद कृति ने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया। साल 2014 में उन्होंने तेलुगु फिल्म '1: नेनोक्काडाइन' से अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म में वह सुपरस्टार महेश बाबू के साथ नजर आईं। इसके बाद उसी साल उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म 'हीरोपंती' से उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार मिला।

इसके बाद कृति ने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। वह शाहरुख खान और वरुण धवन के साथ फिल्म 'दिलवाले', आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव के साथ 'बरेली की बर्फी', कार्तिक आर्यन के साथ 'लुका छुपी' और अक्षय कुमार के साथ 'हाउसफुल 4' जैसी फिल्मों में नजर आईं। 'बरेली की बर्फी' में उनके छोटे शहर की लड़की वाले किरदार को काफी पसंद किया गया।कृति के करियर का सबसे बड़ा मोड़ साल 2021 में आई फिल्म 'मिमी' रही। इस फिल्म में उन्होंने सरोगेट मां का किरदार निभाया था। इस भूमिका के लिए उन्होंने अपना वजन भी बढ़ाया और खुद को पूरी तरह किरदार में ढाला। उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। इसके अलावा उन्होंने फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीता। इसके बाद कृति ने लगातार अलग-अलग तरह के किरदार चुने। 'भेड़िया', 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया', 'क्रू' और 'दो पत्ती' जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता दिखाई। 'दो पत्ती' के साथ उन्होंने बतौर निर्माता भी नई शुरुआत की और अपने प्रोडक्शन हाउस ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स की शुरुआत की। आज वह फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती है।

## 'काला हिरण' पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: सोशल मीडिया से टीजर हटाने का निर्देश

नई दिल्ली/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के बीच चल रहे विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब पर मौजूद फिल्म से जुड़े लिंक हटाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने फिल्म के निर्माता अमित जानी के रवैये पर भी नाराजगी जताई और उन्हें कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने अमित जानी के वकील से कहा कि ऐसा लगता है कि पिछली सुनवाई में कोई आदेश पारित नहीं होने पर आपको हिम्मत मिल गई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ''आपको इस बात से हिम्मत मिल रही है कि पिछली बार कोई आदेश पारित नहीं हुआ था। आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं। आप दिन-प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। आप किसी आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते।'' अदालत ने फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट को लेकर नाराजगी जाहिर की।

सुनवाई के दौरान अमित जानी की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि अभी केवल फिल्म का टीजर जारी किया गया है और इससे किसी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। उन्होंने कहा, ''यह सिर्फ एक टीजर है। इसमें कहीं भी सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है। इसमें कोई डीपफेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार किया गया वीडियो भी नहीं है। सार्वजनिक घटनाओं पर आधारित कहानी दिखाने पर किसी का विशेष अधिकार नहीं हो सकता।''वहीं, सलमान खान की ओर से पेश वकील ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि फिल्म में भले ही नाम न लिया गया हो, लेकिन अभिनेता की पहचान और छवि का स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि सलमान खान के खिलाफ दर्ज चार मामलों में से तीन में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है, जबकि एक मामले में सजा पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद फिल्म में उन्हें ऐसे पेश किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि प्रभावित हो सकती है।सलमान के वकील ने यह भी कहा कि फिल्म के जरिए पूरे बिश्नोई समाज को अभिनेता के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।

सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स और यूट्यूब पर मौजूद फिल्म के टीजर और उससे जुड़े सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया। दरअसल, यह पूरा विवाद फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के फर्स्ट लुक पोस्टर से शुरू हुआ था। पोस्टर में अभिनेता काशिफ इकबाल खान का लुक सलमान खान से काफी मिलता-जुलता दिखाई दिया। उन्हें सलमान की तरह नीले रंग का मशहूर ब्रेसलेट पहने भी दिखाया गया था। बाद में रिलीज हुए टीजर में भी अयान खान नाम का किरदार दिखाया गया, जिसे सलमान खान से प्रेरित माना जा रहा है। वहीं, फिल्म में लॉयन बिश्नोई नाम का किरदार भी है, जिसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित बताया जा रहा है। हालांकि, फिल्म के निर्माता लगातार यह दावा करते रहे हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित फिल्म नहीं है।

# विफा के तिरुचि चैप्टर और जोन 17-बी की बैठक सम्पन्न, पदाधिकारियों की नियुक्ति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुचि। विप्र फाउंडेशन तिरुचि चैप्टर और जोन 17 बी तमिलनाडु की बैठक राजपुरोहित समाज भवन में आयोजित की गई। चैप्टर के अध्यक्ष जोग सिंह राजपुरोहित ने स्वागत भाषण में क्षेत्रीय महामंत्री (दक्षिण) भगवान व्यास एवं जोन के अध्यक्ष किशोर कुमार शर्मा तथा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और उनके 4 वर्षों के कार्यकाल में मिले सहयोग के लिए सभी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का आयोजन सफल हुआ था।किशोर शर्मा ने संगठन के महत्व पर प्रकाश डाला और भगवान व्यास ने विफा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सर्वसम्मिति से तिरुचि चैप्टर की नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष रूपचंद राजपुरोहित, सचिव दिनेश राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष किशोर सिंह राजपुरोहित, उपाध्याय मंगल सिंह राजपुरोहित, सहमन्त्री उमेश सिंह राजपुरोहित एवं अर्जुन सिंह राजपुरोहित को दायित्व सौंपा गया। दिनेश राजपुरोहित ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

# जीवन का वास्तविक मूल्य धन वैभव से नहीं गुण वैभव से आंका जाता है : कपिल मुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

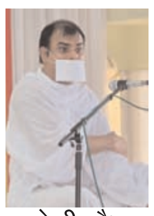

चेन्नई। यहाँ चूले में मणिक्कम स्ट्रीट स्थित लक्ष्मी महल में चातुर्मासार्थ विराजित श्री कपिल मुनिजी म. सा. ने आयोजित चातुर्मासिक प्रवचन माला के तहत मंगलवार को कहा कि संत समागम, जिनवाणी का श्रवण और धर्माराधना का अवसर प्रबल पुण्य से मिलता है। इसे सहज में मिलने वाली चीज समझने की गलती न करें। मनुष्य उसी वस्तु का मूल्य समझता है, जो कठिन परिश्रम और लंबे इंतजार के बाद प्राप्त होती है। जो वस्तु सहज मिल जाती है, उसकी कद्र प्रायः नहीं होती। हीरा इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि वह दुर्लभ है यदि वह मिट्टी की तरह सर्वत्र मिल जाता तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार संतों का सान्निध्य और जिनवाणी का श्रवण भी जीवन के दुर्लभतम रत्न हैं। जो इनके मूल्य को नहीं पहचानते, वे वास्तव में अपने ही सौभाग्य को खो देते हैं। देव, गुरु और धर्म का समागम प्रकष्ट पुण्य का परिणाम है। कितने ही जीव ऐसे हैं जिन्हें धर्म का नाम सुनने का अवसर भी नहीं मिलता। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है पर सत्य का मार्ग दिखाने वाला सद्गुरु नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है मनुष्य अपने घर की प्रत्येक वस्तु का बड़ा ध्यान रखता है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि झाड़ कहाँ रखनी है, चाबी कहाँ रखनी है, आवश्यक दस्तावेज कहाँ रखने हैं और सोने-चाँदी के बहुमूल्य आभूषणों को किस तिजोरी में सुरक्षित रखना है। वह लाखों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करता है। परंतु आश्चर्य यह है कि जिस जीवन के कारण यह सब कुछ है, उसी जीवन का मूल्य समझने में वह चूक जाता है। जीवन का वास्तविक मूल्य धन, भवन या बैंक बैलेंस से नहीं आँका जाता। जीवन का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि हमने प्रभु वाणी का रसपान करके जीवन मे कितना गुणात्मक परिवर्तन किया कितने लोगों के जीवन में प्रकाश पहुँचाया।

# 'मनुष्य जन्म भगवान बनने की संभावना का स्वर्णिम अवसर, चातुर्मास उसका सर्वोत्तम साधन'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। वेपेरी श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ में चातुर्मासार्थ विराजित आचार्यश्री कुलबोधिसूरिश्वरजी म.सा. के पावन सान्निध्य में मंगलवार को चातुर्मास का शुभारंभ श्रद्धा, उत्साह एवं धार्मिक वातावरण के बीच हुआ। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष तेजराज कोठारी, उपाध्यक्ष चंपालाल रांका तथा सचिव संघवी आकाश जैन सहित संघ के पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं ने आचार्यश्री का भावपूर्ण स्वागत किया। गौतम किरण परिसर में आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्यश्री ने कहा कि तन को वासना में लगाने के लिए अनंत-अनंत भव मिल सकते हैं, किन्तु साधना के लिए मनुष्य जन्म जैसा दुर्लभ अवसर पुनः सहज उपलब्ध नहीं होता। इसी मनुष्य जन्म में दो महान संभावनाएं निहित हैं, या तो स्वयं भगवान बन सकते हैं अथवा भगवान के सच्चे भक्त और अनुयायी बन सकते हैं। उन्होंने प्रेरणा दी कि यदि महावीर बनना संभव न हो तो कम से कम ऐसा जीवन जिएं कि भगवान के बन सकें।

आचार्यश्री ने कहा कि संघ के बिना साधु अधूरा है और साधु के बिना संघ। शासन की धुरी संघ है और संघ की धुरी साधु है। उन्होंने बताया कि महावीर निर्वाण के लगभग 650 वर्ष बाद साधु स्थायी रूप से नगरों में आने लगे क्योंकि संघों को उनके सतत मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। अपने प्रवचन में आचार्यश्री ने चातुर्मास को सफल बनाने के लिए पांच प्रेरक सूत्र प्रस्तुत किए नेवर (धर्म के निकट आना), हियर (जिनवाणी सुनना), डियर (देव-गुरु के प्रति अपनत्व), फियर (पाप का भय) और टियर (भक्ति के अश्रु)। उन्होंने कहा कि चातुर्मास धर्म के समीप आने और आत्मपरिवर्तन का अनुपम अवसर है। अनंत भवों के बाद प्राप्त जिनवाणी का श्रवण प्रमाद रहित होकर करना चाहिए। गौतमस्वामी ने प्रभु के समीप रहकर जिनवाणी सुनी, जबकि दुर्योधन ने श्रीकृष्ण की बात नहीं मानी और अर्जुन ने उसे आत्मसात किया, परिणामस्वरूप विजय अर्जुन की हुई। उन्होंने सभी से प्रतिदिन कम से कम एक घंटा जिनवाणी श्रवण के लिए समर्पित करने का आह्वान किया।

# चातुर्मास आत्मशुद्धि, संयम और साधना का स्वर्णिम अवसर : आचार्य हीरचंद्रसूरिश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां श्री चंद्रप्रभु जैन नया मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में चातुर्मासार्थ विराजित आचार्यश्री हीरचंद्रसूरिश्वरजी म.सा. के सान्निध्य में मंगलवार को चातुर्मास का शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और धर्ममय वातावरण के बीच हुआ। धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्यश्री हीरचंद्रसूरिश्वरजी म.सा. ने कहा कि शास्त्रों में कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इन तीन चातुर्मासों का उल्लेख मिलता है। इनमें आषाढ़ चातुर्मास विशेष आराधना का काल है। इस अवधि में अभिग्रह, प्रवचन श्रवण, स्वाध्याय एवं अन्य धार्मिक साधनाओं के माध्यम से आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पूरे चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन प्रातः 6.15 बजे 'तत्त्वार्थधिगम सूत्र' की वांचना होगी। यह ग्रंथ सरल, सहज एवं जीवनोपयोगी होने के कारण प्रत्येक श्रावक-श्राविका के लिए अत्यंत लाभदायक है।

पंन्यास विमलपुण्य विजयजी म.सा. ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि धर्म आराधना द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव, इन चारों की अनुकूलता के साथ करनी चाहिए। चातुर्मास धर्मसाधना के लिए सर्वश्रेष्ठ काल और क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन प्रातः वांचना, प्रातः 9.15 बजे प्रवचन तथा रात्रि 8.30 बजे रात्रिकालीन प्रवचन होंगे। उन्होंने कहा कि चातुर्मास में होने वाले प्रत्येक अनुष्ठान, तप और धार्मिक क्रिया का लक्ष्य आत्मा की शुद्धि होना चाहिए।

पंन्यासश्री ने बताया कि मंगलवार का दिन दादागुरुदेव जगच्चंद्रसूरिजी म.सा. की 75वीं दीक्षा वर्षगांठ के रूप में भी अत्यंत गौरवपूर्ण है।

# तीन दिवसीय 'सिगा फेयर-2026' का हुआ शुभारंभ

## 150 से अधिक ब्रांड कर रहे हैं उत्पादों का प्रदर्शन / इस बार का फेयर महिला उत्पादों पर केन्द्रित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। दक्षिण भारत के गारमेंट एवं फैशन उद्योग के एक प्रतिष्ठित साउथ इंडिया गारमेन्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में पैलेस ग्राउंड के प्रिंसेस श्राइन सभागार में मंगलवार को तीन दिवसीय 31वां 'सिगा फेयर -2026' का आगाज हुआ। गारमेंट बाजार के बहुप्रतीक्षित इस ट्रेड फेयर में देशभर के 150 से अधिक प्रतिष्ठित गारमेंट एवं फैशन ब्रांड्स ने अपने नवीनतम कलेक्शन और आगामी सीजन के ट्रेंड्स के अनुसार उत्पादों का प्रदर्शन किया। मेले में अलग अलग राज्यों के 35 स्टोर शामिल हुए। पहली बार साउथ इंडिया गारमेंट्स एसोसिएशन में महिलाओं के कपड़ों को खास प्राथमिकता दी गई है। ट्रेड फेयर के पहले दिन मॉडलों ने महिलाओं के कपड़ों, फेस्टिवल और ब्राइडल वियर की अनेक नई डिजाइनों का लाइव प्रदर्शन किया। इस फेयर में महिला, पुरुष वर्ग सहित किड्स वेयर के साथ साथ पारम्परिक विवाह, केजुअल व फार्मल्स, डेनिम, वेस्टर्न, लाउंज, विंटर वियर की विस्तृत रेंज प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा गारमेन्ट उद्योग से जुड़े साफ्टवेयर, एकाउटिंग सिस्टम, उपकरण, मशीन व कच्चे माल से संबंधित स्टाल भी लगाए गए हैं।

दावणगेरे के चन्नाबसप्पा एंड संस के मालिक बीसी शिवकुमार ने इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिगा के अध्यक्ष अनुराग सिंगला, क्लाथिंग मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव नवीन सैनानी, गुजरात गारमेन्ट मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पुरोहित, दिया डिजाइनिंग स्टूडियो मुम्बई के संस्थापक दिनेश झालानी, अभिनेत्री प्रियंका अरोड़ा सहित सिगा के उपाध्यक्ष नरेश लखनपाल व राजेश चावत, मंत्री तेजस मेहता व कोषाध्यक्ष व फेयर चेयरमैन गोविंद मूंदड़ा उपस्थित थे।

उद्घाटन के मौके पर चन्नाबसप्पा एंड संस के मालिक बीसी शिवकुमार ने कहा कि इस तरह के ट्रेड फेयर व्यापारियों व उद्योग के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ऐसे ट्रेड फेयर में नए-नए डिजाइन देखने, नए ग्राहकों को ढूंढने व अपनी जरूरत के अनुसार ब्रांड्स खरीदने का अवसर मिलता है।

अनुराग सिंगला ने कहा कि कैजुअल, फॉर्मल कपड़े, विंटर कपड़े, फैशन के कपड़े इस बार के ट्रेड फेयर की खासियत हैं। उन्होंने कहा कि यह ट्रेड फेयर केवल एक प्रदर्शनी नहीं अपितु भारतीय गारमेंट उद्योग के लिए बिजनेस ग्रोथ नेटवर्किंग और नए अवसरों का सशक्त प्लेटफार्म सिद्ध होता है।

उन्होंने कहा कि गुरुवार तक चलने वाले इस मेले में लगभग पांच हज़ार से ज़्यादा ट्रेडर्स के शामिल होने की उम्मीद है और ज़्यादा व्यापार के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। उपाध्यक्ष नरेश लखनपाल ने कहा कि इस बार के मेले में महिलाओं को केन्द्रीत कर आयोजन किया गया है। ट्रेड फेयर के पहले दिन बड़ी संख्या में संभावित ग्राहकों की भीड़ देखी गई।

# बच्चों में संस्कार आवश्यक है : पंन्यासश्री आगमशेखर विजय

कोयम्बटू/दक्षिण भारतर। यहां के आरजी स्ट्रीट स्थित श्री राजस्थान जैन श्वेताबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा संचालित बड़ा सुपार्श्वनाथ मंदिर में पन्यासश्री आगमशेखर विजयजी के मंगलवार को अपने प्रवचन में कहा कि आज अधिकांश जैन संघों में चातुर्मास के दौरान प्रवचन, पूजा, तप, आराधना, भक्ति, शोभायात्रा और अनेक धार्मिक आयोजन के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम बच्चों के लिए नियमित संस्कार वर्ग को अनिवार्य स्थान देते हैं? यह चिंतन का विषय है। बच्चें आज केवल परिवार के उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि धर्म के भी उत्तराधिकारी हैं। यदि उन्हें बचपन में धर्म का परिचय नहीं मिलेगा, तो बड़े होकर केवल नाम के जैन रह जाएंगे, व्यवहार के नहीं।

उन्होंने कहा कि धर्मशालाएँ, मंदिर और आयोजन स्थल समाज की धरोहर हैं, लेकिन सबसे बड़ी धरोहर संस्कारित बालक हैं। भवन धन से बनते हैं, जबकि चरित्र संस्कारों से बनता है। संस्कार वर्ग वैकल्पिक नहीं, आवश्यक धार्मिक व्यवस्था बने। बच्चों को केवल कहानी नहीं, जीवन जीने की कला सिखाई जाए। संचालन हितेश संघवी ने किया बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

### सहयोग

जेसीआई बेंगलूरु कॉस्मो के प्रतिनिधि मंडल ने निम्हांस अस्पताल के रजिस्ट्रार हर्षा एएच से शिष्टाचार भेंट कर सामाजिक सेवा के अंतर्गत व्हीलचेयर व रॉक बेंच दान देने के घोषणा की तथा लिखित सहमति दी। प्रतिनिधिमंडल में सचिव रीना गांधी, ज़ोन ऑफिसर मोनिका कुमट एवं रूपचंद कुमट शामिल थे।

# आषाढ़ी चातुर्मासी पर्व तप-त्याग पूर्वक मनाया

चेन्नई। यहां बेसिन वाटर वर्क्स स्ट्रीट साहूकारपेट में स्थित स्वाध्याय भवन में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी चातुर्मासी पर्व जप-तप-त्याग पूर्वक मनाया गया। इस प्रसंग पर वरिष्ठ स्वाध्यायी वीरेन्द्र कांकरिया ने प्रश्न व्याकरण सूत्र आगम का वांचन किया। प्रश्न व्याकरण आगम के चतुर्थ ब्रह्मचर्य संवर के अंतर्गत माहात्म्य और स्वरूप, बत्तीस उपमाएं, ब्रह्मचर्य के घातक निमित्त, ब्रह्मचर्य रक्षक नियम, पांच भावनाएं विविक्त शयनासन, स्त्री कथा वर्जन, रुप दर्शन का त्याग, पूर्व भोग चिन्तन त्याग पर विस्तृत विवेचन किया। स्वाध्यायी बन्धुवरों ने अष्ठ प्रहर पौषध,एकासन आदि नियम किये व संवर प्रतिक्रमण करते हुए सर्व जीव राशि से क्षमा याचना व चोवीसी स्तुति की। रत्न हितैषी श्रावक संघ से आर नरेन्द्र कांकरिया ने चिन्तन सूत्र कमल चोरडिया ने मनोरथ चिन्तन इंदरचंद कर्णावट ने प्रत्याख्यान कराए। वरिष्ठ श्रावक सोहनलाल झामड ने मंगल पाठ किया। आषाढ़ी चातुर्मासिक पर्व पर स्वाध्यायीगण की सामायिक परिवेश में प्रमोदजन्य उपस्थिति रही। धार्मिक-आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ आषाढ़ी चातुर्मासी पर्व सम्पन्न हुआ।

# जीवन में परिवर्तन ही धर्म का पहला सूत्र : जयतिलकमुनि

चेन्नई। एसएस जैन संघ, सौकारपेट के तत्वावधान में जैन भवन में आयोजित चातुर्मासिक प्रवचन में गुरुदेव श्री जयतिलक मुनि जी म.सा. ने उपस्थित श्रद्धालु श्रावक-श्राविकाओं को धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाते हुए कहा कि जीवन में परिवर्तन ही धर्म का पहला सूत्र है। धर्म केवल किसी विशेष अवसर या समय का विषय नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनाई जाने वाली साधना है। गुरुदेव ने कहा कि धर्म वर्ष के बारहों महीने किया जाना चाहिए, किन्तु चातुर्मास के चार महीनों को धर्म, तप, त्याग और आराधना के लिए सर्वोपरि माना गया है। तीर्थंकर परमात्मा ने साधु-साध्वियों के साथ-साथ श्रावक-श्राविकाओं को भी इन पवित्र महीनों में विशेष रूप से धर्मक्रियाओं से जुड़ने की प्रेरणा दी है। उन्होंने बताया कि भगवान ने साधुओं के लिए नौ कल्प तथा साध्वियों के लिए पाँच कल्प का विधान किया है। प्रवचन में गुरुदेव ने कहा कि धर्म ही जीव को संसार के जन्म-मरण के चक्र से मुक्त कर मोक्षमार्ग की ओर अग्रसर करता है। इस अवसर पर साहुकारपेट के एसएस जैन संघ के अध्यक्ष डॉ. संजय पिंचा ने कहा कि प्रत्येक श्रावक-श्राविका को अधिकाधिक धर्म से जुड़कर चातुर्मास का सदुपयोग करना चाहिए। सभा का संचालन संघ के उपाध्यक्ष सर्जनराज सुराना ने किया तथा सभी से तप, त्याग और धर्म आराधना में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

# एफटीएस युवा 9 अगस्त को कर रहे हैं मेगा रक्तदान शिविर

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल्स सोसाइटी (एफटीएस) युवा द्वारा आगामी 9 अगस्त को महाराजा अग्रसेन भवन में मेगा रक्तदान महाअभियान का आयोजन अपोलो हॉस्पिटल्स, नारायणा हेल्थ, एस्टर हॉस्पिटल्स एवं संकल्प इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। युवा सचिव विकास गुप्ता ने बताया कि इस महाअभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना तथा जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। महाअभियान के संयोजक आयुष अग्रवाला, शुभम लोहिया, प्रवीण गेहलोत एवं अरुण शर्मा ने अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इस रक्तदान शिविर की तैयारियों के लिए बैठकों का दौर चल रहा है ।

# मन के शुद्धिकरण करने का समय है चातुर्मास : साध्वी प्रियश्रद्धांजनाश्री

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के जिनकुशलसूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट बसवनगुड़ी के तत्वावधान में साध्वी डॉ प्रियश्रद्धांजनाश्रीजी ने चातुर्मास के प्रथम दिवस चातुर्मासिक चतुर्दशी के प्रवचन में कहा कि आज का मंगलमय प्रभात एक अनूठा प्रकाश पुंज लेकर हमारे बीच आया है। चार मास के लिए चारों ओर से जहां जीवों की उत्पत्ति होती है इसलिए साधु साध्वी, श्रावक व श्राविकाओं को इस काल में आराधना साधना में स्थिर हो जाना है। इस काल में बाह्य जगत से हमें अन्तर्जगत और आध्यात्मिक जगत में डूबना है। इन सभी चीजों में उतरने के लिए हमारे मन की शुद्धि आवश्यक है। आज से हमारा आचार विचार और वाणी बदल जानी चाहिए। सर्वप्रथम हमारे परिवार में शान्ति होनी चाहिए, द्वितीय हमें हमारे जीवन में हर समय में हर परिस्थिति में समभाव में ही रहना है। तृतीय हमें हर प्रकार की छोटी बड़ी तपस्याएं आडम्बर रहित करनी है। चतुर्थ सभी को जिनवाणी श्रवण के दौरान सामायिक आसन धारण करना चाहिए। आराधना करने से हमारा चरित्र मोहनीय कर्म टूटता है। परमात्मा ने श्रावक-श्राविकाओं को धर्म में स्थिर करने और पाप प्रवृत्तियों का निषेध करने हेतु चातुर्मास की स्थापना की है। चातुर्मास में सर्वप्रथम हमें हमारे मन का शुद्धिकरण करना है। प्रवचन के दौरान साध्वीश्री द्वारा वांचन किए जाने वाले 'ध्यान शतक ग्रंथ' को प्रदान किया गया जिसका लाभ मंजूदेवी मदनलाल बाफना परिवार, चरित्र वांचन में जैन रामायण ग्रंथ का प्रदान करने का लाभ शांतिदेवी पुखराज तेजराज गुलेच्छा परिवार ने लिया। चातुर्मास प्रारंभ होने के साथ ही मंगलवार से माणिक्य स्वामी तप का प्रारंभ हुआ जिसमें दो सौ से अधिक तपस्यार्थी तपस्या कर रहे हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

### शिक्षा सेवा

बेंगलूरु के मानव सेवा समिति के सदस्यों ने जून-जुलाई के मानवसेवी कार्य के अंतर्गत बोमसन्द्रा, तुमकूर, राजाजीनगर, उर्दीगेरे व कोरटीगेरे के 85 स्कूलों के 8200 स्कूली बच्चों को कुल 22 हजार अभ्यास पुस्तिकाएं, पाठ्य सामग्री, ज्योमेट्री बॉक्स व चॉकलेट बांटे गए। इस सेवा कार्य में विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षकों व स्कूल इंस्पेक्टर वासुदेवाचार्य का सहयोग प्राप्त हुआ। समिति के सदस्यों ने अपने हाथों से विभिन्न स्कूली बच्चों को सहयोग सामग्री बांटी।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.